



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2019/भाद्र 28, 1941

No. 286]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2019/ BHADRA 28, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय : बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये पटसन उत्पादों अर्थात् पटसन यार्न/ द्वाइन (बहु परत वाले/ केबल किया हुआ और एकल) हैसियन फेब्रिक और पटसन यार्न के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क जैसा कि दिनांक 27.03.2018 किये गये मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) और मैसर्स एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी (निर्यातक/ व्यापारी), यू एस ए द्वारा अनुरोध किया गया है, के संबंध में सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अंतर्गत नई शिपर समीक्षा ।

सं. 7/7/2018-डी जी ए डी.—सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) तथा उसके सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया (इसके पश्चात "नियमावली के रूप में भी संदर्भित") के संबंध;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. जबकि, मूल पाटनरोधी जांच में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) ने अन्य बातों के साथ साथ दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/19/2015 – डी जी ए डी के संदर्भ में सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 69 के अंतर्गत आने वाले बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा से निर्यात किये गये “पटसन उत्पादों” अर्थात् पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाले/ केबल किया हुआ और एकल), हैसियन फेब्रिक और पटसन सेकिंग थैले के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने दिनांक 05 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) – सीमा शुल्क तथा दिनांक 03 अप्रैल, 2017 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के संदर्भ में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को अधिसूचित किया।
3. मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) और मैसर्स एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी (निर्यातक/ व्यापारी), यू एस ए सीमा प्रशुल्क अधिनियम के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के संबंध में नई शिपर समीक्षा (एन एस आर) के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें बंगला देश के मूल के अथवा वहां निर्यात किये गये “पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाला/ केबल किया हुआ और एकल) और पटसन सेकिंग थैले” जिसमें दिनांक 03 अप्रैल, 2017 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के संदर्भ में “पटसन उत्पादों” पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, के आयातों के संबंध में अलग अलग पाटन मार्जिन का दावा करते हुए नई शिपरसमीक्षा (एन एस आर) का अनुरोध किया गया है।
4. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) और मैसर्स एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी (निर्यातक/ व्यापारी), यू एस ए के संबंध में बंगला देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाला/ केबल किया हुआ और एकल) और पटसन सेकिंग थैले” के पाटित आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण के उद्देश्यों से अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए दिनांक 27 मार्च, 2018 के अधिसूचना संख्या 7/7/2018 – डी जी ए डी के संदर्भ में नई शिपरसमीक्षा जांच शुरू की।
5. वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 मई, 2018 के अधिसूचना सं. 24/2018 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के संदर्भ में उपर्युक्त एन एस आर जांच के पूरा होने तक मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) और मैसर्स एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी (निर्यातक/ व्यापारी), यू एस ए द्वारा किये गये संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातों पर अनंतिम आकलन को अधिसूचित किया।
6. इस नई शिपरसमीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के रूप में निर्धारित किया गया था।

ख. प्रक्रिया

7. नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन वर्तमान जांच के संबंध में किया गया है :
 - (i) प्राधिकारी ने संबद्ध एन एस आर पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 27 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. 7/7/2018 – डी जी ए डी के संदर्भ में एक आम सूचना जारी की।
 - (ii) प्राधिकारी ने आवेदक को निर्यातक की प्रश्नावली की एक प्रति के साथ साथ जांच शुरुआत से संबंधी अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें जांच की अवधि के समाप्त होने के बाद निर्धारित प्रश्नावली में सभी संगत आंकड़े प्रस्तुत करने और लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अवसर दिया।

- (iii) प्राधिकारी ने भारत में बंगला देश के उच्चायोग को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भी अग्रेषित की।
- (iv) प्राधिकारी ने भारत में ज्ञात घरेलू उत्पादकों को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें अपने विचार लिखित रूप में अवगत कराने के लिए अवसर दिया।
- (v) जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर, प्रश्नावली का उत्तर मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) और मैसर्स एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी (निर्यातक/ व्यापारी), यू एस ए द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो भारत में “पटसन उत्पादों” के घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में भी अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे।
- (vi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुरोधों/ सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- (vii) प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने के लिए और उसके बाद लिखित अनुरोधों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 8 जुलाई, 2019 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों/ सूचना के संबद्ध में खंडन संबंधी उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- (viii) इस जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये सभी संगत अनुरोधों/ टिप्पणियों पर विचार किया गया है और उन्हें इस प्रकटन विवरण में शामिल किया गया है।
- (ix) इस जांच की प्रक्रिया के दौरान और प्रकटन विवरण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये सभी संगत अनुरोधों/ टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- (x) प्राधिकारी भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 30 अगस्त, 2019 को एक प्रकटन विवरण जारी किया।
- (xi) इस विवरण में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार की गई सूचना को द्योतक है।
- (xii) 70.82 रुपए प्रति यू एस डॉलर के विनिमय दर को जांच की अवधि के लिए लिया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

8. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद ‘पटसन उत्पाद’ है पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाला/ केवल किया हुआ और एकल), हैसियन फेब्रिक और और पटसन सेकिंग थैले से बने हुए हैं। प्राधिकारी ने उत्पादकों को मूल जांच में प्रत्येक प्रकार के पटसन उत्पादों के लिए अलग अलग शुल्क की सिफारिश की थी।
9. वर्तमान जांच इस अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उनके द्वारा दायर किये गये आवेदन के अनुसार मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) और मैसर्स एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी (निर्यातक/ व्यापारी), यू एस ए द्वारा पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाला/ केवल किया हुआ और एकल) और पटसन सेकिंग थैले (दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के अंतिम जांच परिणामों में यथाउल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत दो उत्पाद प्रकारों में से) के प्रस्तावित निर्यातों से संबंधित है।

घ. विभिन्न अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

10. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध :

- i. आई जे एम ए यह अनुरोध करता है कि आवेदक ने प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“ए डी ए”) नई शिपर समीक्षाओं जो पिछले पांच वर्ष में लागू रही हैं और नई शिपर समीक्षा के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी और सेस्टेट के निर्णयों के संबंध में निदेशालय की समग्र के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन के संबंध में पाटनरोधी नियमावली और करार, इस अधिनियम के संबंध में पर्याप्त और आवश्यक सूचना प्रदान किये बिना वर्तमान जांच शुरुआत की मांग की है।
- ii. यह जांच 18 जनवरी, 2018 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने 25 अप्रैल, 2018 को इस मामले की जांच शुरू करने के पूर्व भी एन एस आर जांच के लिए नया प्रश्नावली प्रपत्र बनाया था। जबकि यह समझा जाता है कि यह याचिका व्यापार सूचना के जारी किये जाने के पूर्व दायर किया गया होगा, फिर भी आवेदक का यह दायित्व था कि वह जांच की शुरुआत के बाद व्यापार सूचना के अनुसार अद्यतित सूचना प्रस्तुत करे। पर्याप्त समय और जानकारी रहने के बावजूद, आवेदक ने नये आवेदन प्रपत्र के अनुसार सूचना में संशोधन नहीं किया। यह देखना आश्चर्यजनक है कि मांगी गई बाढ़ की जांच की अवधि के लिए दायर किये गये प्रश्नावली का उत्तर (व्यापार सूचना के जारी किये जाने के बहुत बाद) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर विचार नहीं करता है।
- iii. यह दावा किया गया है कि कंपनी को मूल जांच की जांच की अवधि के बाद निगमित किया गया था। जो अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक है के बाद शामिल किया गया है। हालांकि, निगमन का प्रमाणन दर्शाते हुए साक्ष्य से यह पता चलता है कि कंपनी को 3 दिसंबर, 2014 को निगमित किया गया था। इससे यह पता चलता है कि कंपनी को मूल जांच की जांच अवधि के निगमित किया गया हालांकि इसके संबंध में दावा अन्य प्रकार से किया गया है। इस प्रकार से यह दर्शाने की जिम्मेदारी कि इसने मूल जांच की जांच की अवधि के दौरान वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, बढ जाता है।
- iv. इसके अलावा, आज की तारीख तक इस याचिका में यह ‘दर्शाने’ के लिए किसी सूचना और साक्ष्य का अभाव है कि आवेदक नियम 22 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस कारण से वर्तमान जांच को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- v. जबकि एक विश्वसनीय नई शिपर का यह अधिकार है कि वह अलग अलग मार्जिन की मांग करे उसके साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात का पता लगाने की आवश्यकता है कि यह दावे विश्वसनीय हैं और पाटनरोधी शुल्कों का कोई दुरुपयोग/ हानि / प्रवंचना नहीं है। यह इस कारण से है कि आवेदक को इस तथ्य को कठोरता से सिद्ध करने की आवश्यकता है कि (क) असली/ विश्वसनीय निर्यातक हैं जिन्होंने विश्वसनीय बिक्री है (ख) उन्होंने मूल जांच में वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है (ग) वे संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक अथवा निर्यातक जिन पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है, से संबंधित नहीं हैं। वर्तमान मामले में आवेदक उनमें से किसी मानदंड को पूरा नहीं करता है।
- vi. आवेदन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है। जैसा कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा एच एंड आर जॉनसन (इण्डिया) लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माना गया है कि “दर्शाना” शब्द का आशय आवेदक द्वारा केवल इस अभिकथन की औपचारिकता मात्र का निर्धारण करना नहीं है की आवेदक “संबंधित” नहीं हैं।
- vii. आवेदक ने यह साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि वे निर्यात करने वाले देश में से किसी भी निर्यातक/ उत्पादक से संबंधित नहीं है जो इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं, उसे सिद्ध करने के लिए

साक्ष्य की बात ही छोड़ दी जाये। इस कानून के अंतर्गत अपेक्षा “दर्शाने के लिए” अर्थात्, “यह प्रदर्शित करने के लिए” और न कि “दावा” करने अथवा “उल्लेख” करने के लिए है।

- viii. आवेदक ने यू एस ए में इसके उत्पाद के लिए और न कि भारत में जहां इसने निर्यात किया है अथवा बंगला देश में जहां उत्पादक अवस्थित है और जहां काफी संख्या में व्यापार हैं, के लिए किसी व्यापारी को सुरक्षित किया है। बंगला देश में किसी उत्पादक को भारत में निर्यात करने के लिए यू एस में पूर्ण रूप से व्यापारी का पता लगाना था।
- ix. आवेदकों ने जांच की अवधि अर्थात् वह अवधि जो नियम 22 के अंतर्गत जांच की शुरुआत की बाद की अवधि है के रूप में बाद की अवधि की मांग की। टाइल्स मामले में जिसमें भावी समीक्षा अवधि की अवधारणा की बहुत अधिक आलोचना की गई, में माननीय सेस्टेट द्वारा निर्णय का संदर्भ लिया जाता है।
- x. जांच की भावी अवधि के कारण, आवेदक (क) केवल औपचारिक निर्यात अर्थात् 163 मी. ट. निर्यात (ख) कृत्रिम रूप से बहुत अधिक कीमत पर कीमत में हेर फेर और उसमें बदलाव करने में सक्षम हुए हैं। यहां यह नोट प्रासंगिक है कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बावजूद, बंगला देश से आयात काफी अधिक मात्रा में हुआ है। हालांकि निर्यातक ने कम मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने का विकल्प अपनाया है जो कुल आयातों की तुलना में बहुत कम है। आवेदक के आचार से यह पता चलता है कि वे वर्तमान मामले के भविष्य के बारे में गंभीर नहीं हैं और वर्तमान प्रयास केवल भाग्य अजमाने के लिए प्रयास करना भर है, यदि उन्हें अनुकूल मार्जिन मिले। उनकी कार्यवाही यह नहीं दर्शाती है कि वे अपने उत्पादों का निर्यात करने के बारे में गंभीर हैं।
- xi. भारत में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री का रद्द न किये जाने योग्य संविदागत करारों के साक्ष्य के संबंध में प्रश्नों के प्रति निर्यातक के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि भावी ग्राहक के साथ कोई प्रतिबंधता अथवा संविदा नहीं है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व इन वस्तुओं का निर्यात करने के लिए कोई गंभीर प्रयास भी नहीं किया गया है।
- xii. एक नई शिपर समीक्षा में जांच की अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा किये गये निर्यात उचित मात्रा में विश्वसनीय वाणिज्यिक लेन देन होना चाहिए और पाटन मार्जिन के लिए आधार कीमत होना चाहिए। यह देखे जाने की आवश्यकता है कि क्या विचाराधीन बिक्री प्रकारात्मक है और यह नई शिपर की भविष्य में की जाने वाली बिक्री का द्योतक होगा। यदि किसी उत्पादक अथवा निर्यातक के लेन देन में कीमत अथवा मात्रा और समग्र परिस्थितियां जिन पर उन बिक्री की वाणिज्यिक व्यावहारिकता पर विचार किये जाने की आवश्यकता है, शामिल हो तब मूल्य और मात्रा दोनों के मामले में उन बिक्री की वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए।
- xiii. अन्य देश के कानूनों जैसे यू एस, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तर्की, ताइवान और वियतनाम आदि के कानूनों को नोट करना इस संबंध में प्रासंगिक है जो यह प्रावधान भी करता है कि निर्यातक द्वारा किया गया लेन देन विश्वसनीय और वाणिज्यिक प्रकृति के होने चाहिए।
- xiv. प्राधिकारी ने विशेष रूप से यह निर्धारित किया गया है कि निर्यातक द्वारा निर्यात की गई मात्राएं वाणिज्यिक मात्रा के रूप में होनी चाहिए जिससे कि पाटन का अलग अलग मार्जिन प्राप्त हो सके। आवेदक ने यह तर्क दिया है कि व्यापार संबंधी सूचना हाल में ही जारी की गई है और इस प्रकार से इसके भविष्य मामलों पर प्रभाव पड़ेगा, यह अनुरोध किया गया है कि दर्शाया गया सिद्धांत एक नया सिद्धांत नहीं है। वास्तविक निर्यात का सिद्धांत वाणिज्यिक मात्रा में किया गया है और इसकी पहचान प्राधिकारी द्वारा तथा माननीय सेस्टेट द्वारा विगत में किया गया है।
- xv. यदि किसी निर्यातक को केवल निर्यात की लघु मात्रा अथवा निर्यातों की प्रत्याशा के आधार पर मार्जिन की अनुमति दी जाती है तब इससे अपेक्षाकृत कम मार्जिन प्राप्त करने के लिए निर्यातक द्वारा कीमतों में हेर फेर करने की गुंजाइश बनी रहेगी।

- xvi. विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, यह इस तथ्य को दबाने के लिए जांच बूझकर किये गये प्रयास की शंका को बल देता है कि एक सांकेतिक निर्यात कम अथवा शून्य पाटन मार्जिन प्राप्त करने के उद्देश्य से अवास्तविक कीमत पर किया गया था और उसके पश्चात आक्रामक रूप से इन मात्राओं का पाटन किया गया था।
- xvii. आवेदकों ने घरेलू उद्योग से सूचना को छिपाने और घरेलू उद्योग को अपने हितों का बचाव करने से रोकने के एकमात्र उद्देश्य से और बिना किसी सही कारण के अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- xviii. आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि किस प्रकार से उनके द्वारा दावा किये गये निर्यात कीमत तर्कसंगत, विश्वसनीय, सांकेतिक है और किस प्रकार से यह निर्यात कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से पर्याप्त है।
- xix. भारत में हुए आयातों की तुलना निर्यात कीमत की विश्वसनीयता को दर्शाने के लिए नहीं की जा सकती है।
- xx. सूचना और साक्ष्य की समुचितता और पर्याप्तता को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकारों के उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत और उत्पादन की लागत दोनों के संबंध में पूर्ण रूप से सूचना अपूर्ण प्रतीत होती है और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उत्पाद प्रकारों में अंतरों को सिद्ध करने के लिए रिकार्ड पर कोई सूचना उपलब्ध है।
- xxi. यदि प्राधिकारी बिना किसी पक्षपात के यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेदक उस शर्त को पूरा करता है और अलग अलग शुल्क न्यायोचित है, तब यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक को मूल जांच में नमूने में शामिल न की गई सहयोगी कंपनियों को देखते हुए भारित औसत शुल्क दिया जा सकता है क्योंकि मूल जांच में नमूना शामिल था।
- xxii. घरेलू उद्योग इस कारण से भी अतिरिक्त रूप से चिंतित हैं कि घरेलू उद्योग के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि बंगला देश के निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य और सूचना की गणवत्ता और मात्रा सभी विगत जांचों में हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहा है।

11. आवेदक उत्पादक/ निर्यातक द्वारा अनुरोध :

- i. आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में यथानिर्धारित एक नई शिपर के रूप में माने जाने के लिए अपेक्षाओं को पूरा करता है जिसका आधार विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 में है। नियम 22 यह कहता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रश्नगत निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत में किसी उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण के उद्देश्य से एक आवधिक समीक्षा करेगा बशर्ते कि ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाते हैं कि ये निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक जो इस उत्पाद के पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन हैं से संबंधित नहीं हैं। आवेदक इन अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- ii. यह दोहराया जाता है कि वर्तमान एन एस आर जांच में आवेदक ने मूल जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया और न ही वे संबंधित हैं और साथ ही या तो नियमावली में यथानिर्धारित अथवा प्रशासनिक व्यापार सूचनाओं के माध्यम से यथा अधिसूचित एन एस आर के संदर्भ संबंध में उनमें यथा अधिसूचित संबद्ध वस्तुओं पर लगने वाले पाटनरोधी शुल्क के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक से 'संबद्ध' के अन्य सभी आशय पर बल दिया गया है।
- iii. नियम 22 की शर्तों की पुष्टि करने के लिए अनुरोध और समानन के अलावा आवेदक ने विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जो कंपनी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की आरंभ तिथि को ब्यौरा और समानन, लेखा परीक्षित रिपोर्ट और अन्य सांविधिक समानन संयंत्र और उपस्करों आदि की खरीद का ब्यौरा शामिल करता है जो आगे नई शिपर आवेदक के दावे को सिद्ध करेगा।

- iv. आवेदक नियम 22 की अपेक्षाओं को पूर्ण से पूरा करता है और उसके आगे यह अनुरोध करता है कि इन पक्षकारों का भारत में सामग्री को पाटित करने कोई उद्देश्य नहीं है और यह बहुत आवश्यक है कि उनके द्वारा किये गये वास्तविक निर्यातों के तथ्यों के आधार पर अलग अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए नई शिपर समीक्षा को उनके वास्तविक निर्यातों को अध्यधीन किया जाये। आवेदक ने निर्धारित जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया है। आवेदकों के मामले में, विचाराधीन उत्पाद का निर्यात जांच की अवधि के दौरान 1100 से 1200 मी. ट. तक हुआ था।
- v. एन एस आर जांच पाटनरोधी करार तथा भारतीय पाटनरोधी नियमावली का अभिन्न हिस्सा है और यह प्रावधान किसी उत्पादक अथवा निर्यातक को एक नये निर्यातक के रूप में अपने मामले को सिद्ध करने के लिए उसमें यथानिर्धारित होने में सक्षम बनाता है जो प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करने में सक्षम बनायेगा कि क्या ऐसे नये निर्यातक द्वारा निर्यातों के मामले में पाटन का कोई कारक है। एन एस आर के विरुद्ध आई जे एम ए के आरोप का कोई आधार नहीं है।
- vi. न तो करार और न ही नियमावली एन एस आर में अलग अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए एक शर्त के रूप में निर्यात की किसी विशिष्ट मात्रा अथवा कीमत का निर्धारण करता है। असंबंधित नई शिपर 'नया' को बनाना सही रूप में इस तथ्य के कारण हुआ है कि मूल जांच की अवधि के दौरान इसने इस प्रक्षेत्र में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जहां संबद्ध वस्तु पाटनरोधी जांच के अध्यधीन थे।
- vii. वास्तव में विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय ने स्पष्ट रूप से पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार समीक्षा किये जाने में मात्रा की आवश्यकताओं को निर्धारित करते हुए बनाये गये किसी कानून के विरुद्ध माना और इस संबंध में चावल पर मेक्सिको – पाटनरोधी शुल्क में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय का निर्णय जी एम एक्सपोर्ट मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ पठित भारतीय प्राधिकार पर बाध्यकारी है।
- viii. विगत कुछ मामलों में, प्राधिकारी ने नये निर्यातक को अलग अलग मार्जिन दिये जाने से इनकार किया है क्योंकि प्राधिकारी ने नये निर्यातक द्वारा निर्यातों की मात्रा को आवेदक उत्पादक/ निर्यातक को अलग अलग पाटन मार्जिन देने के लिए अपनाई जाने वाली वाणिज्यिक रूप से प्रतिनिधि मात्रा के रूप में विचार किये जाने के लिए बहुत कम पाया। हालांकि, वर्तमान मामला यह दर्शाता है कि वर्तमान मामले में मात्रा बहुत अधिक है और इस प्रकार की बहुत अधिक मात्रा से संबंधित निर्यात कीमत को सहज ढंग से विश्वसनीय के रूप में माने जाने की आवश्यकता है।
- ix. वर्तमान मामले में नया शिपर नियम 22 के अनुसार सभी मूल शर्तों और मात्रा की तर्कसंगतता तथा कीमत की विश्वसनीयता दोनों की आवश्यकता के मामले में विगत हाल में प्राधिकारी द्वारा प्रथाओं के भाग के रूप में जारी किये जाने वाले अतिरिक्त शर्तों को भी पूरा करता है।
- x. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कोई भी अलग अलग मार्जिन का निर्धारण यहां नये शिपर के लिए नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में यह मूल मामले में यथा पाये गये 'निर्यातकों का नमूना नहीं लिया गया श्रेणी' पर लागू मार्जिन से छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता है। यह नियम स्पष्ट रूप से यह कहता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक आवधिक समीक्षा करेगा। प्राधिकारी द्वारा मेलामाइन के संबंध में अंतिम जांच परिणामों को प्रकाशित करते समय विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी भी एन एस आर में नमूना न लिये गये श्रेणी के लिए मार्जिन को अपनाने हेतु अपने इस निर्णय के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह 'आवेदक को पाटनरोधी शुल्क की नमूना न ली गई श्रेणी का दर्जा देने के लिए निर्णय लिया था के संबंध में इस मामले के तथ्यों के द्वारा सीमित था'।
- xi. इस प्रकार के बाध्यकारी परिदृश्यों के अंतर्गत अपनाया गया कोई दृष्टिकोण नियम 22 में दी गई स्पष्ट कानूनी स्थिति जिसमें प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह अपने संगत आंकड़ों के आधार पर नई

शिप्परों के लिए अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करे, में स्पष्ट कानूनी स्थिति को देखते हुए एक नियम नहीं बन सकता है।

- xii. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस जांच को 18 जनवरी, 2018 को शुरू किया गया था, जो सही नहीं है। यह मामला 27.3.2018 को शुरू किया गया था। उसके बाद, यह तर्क दिया गया है कि पर्याप्त समय और जानकारी होने के बावजूद आवेदक ने नये आवेदन प्रपत्र के अनुसार सूचना में संशोधन नहीं किया। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। सामान्य अनुदेश में बिंदु सं. 2 पर नया प्रपत्र यह कहता है कि “इस प्रश्नावली को नई शिपर समीक्षा जांचों को शुरू करने के लिए नये उत्पादक/ निर्यातक द्वारा भरा जाना है।” वर्तमान मामले में यह याचिका नये प्रपत्र को शुरू किये जाने के पूर्व दायर किया गया था और जब यह मामला नये प्रपत्र को शुरू किये जाने के पूर्व शुरू किया गया था। नये प्रपत्र को दिनांक 25.04.2018 की व्यापार संबंधी अधिसूचना के संबंध में लागू किया गया था। स्पष्ट तौर पर इस प्रपत्र का बाद का प्रभाव था और यह वर्तमान आवेदकों पर लागू नहीं था।
- xiii. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह दावा किया गया है कि कंपनी को मूल जांच की जांच अवधि के बाद निगमित किया गया है, हालांकि, निगमन के प्रमाणन को दर्शाते हुए साक्ष्य यह दर्शाता है कि कंपनी का निगमन 3 दिसंबर, 2014 को किया गया था, जो यह दर्शाता है कि कंपनी को मूल जांच की जांच अवधि के दौरान निगमित किया गया था, हालांकि इसमें अन्य प्रकार से दावा किया है। यह विवाद स्पष्ट तौर पर आवेदन में प्रश्न 3 एच पर उत्तर में टंकण संबंधी त्रुटि का परिणाम है। याचिकाकर्ता का उद्देश्य यह उल्लेख करना था कि विचाराधीन उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन मूल जांच की जांच अवधि के बाद शुरू हुआ यद्यपि इस कंपनी को मूल जांच की अवधि के दौरान निगमित किया गया था। यह स्पष्ट रूप से मूल आवेदन के प्रश्न सं. 5 में उल्लेख किया गया है जिसे इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है कि “मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमि. बंगला देश की स्थापना 3 दिसंबर, 2014 को पटसन यार्न का उत्पादन करने के लिए किया गया था और पटसन यार्न का उत्पादन 8 अगस्त, 2017 को ही शुरू हुआ।” यह दोहराया जाता है कि कंपनी ने मूल जांच की अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया और इसने 2017 में ही उत्पादन शुरू किया है यद्यपि इसे 2014 में निगमित किया गया था।
- xiv. आई जे एम ए का यह तर्क कि वर्तमान एन एस आर नियम 22 की शर्त को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्यों के बिना शुरू किया गया था, का इनकार इसलिए किया जाता है कि इसमें कोई आधार नहीं है। इस याचिका में यह दर्शाने के लिए साक्ष्य निहित था कि नई शिपर ने मूल जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया और नई शिपर किसी उत्पादन अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं है जिस पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा हो। इसके साथ ही तब से बहुत समय बीत चुका है जब से वर्तमान मामले की जांच शुरू की गई है और घरेलू उद्योग इन आवेदकों के दावे का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
- xv. भावी जांच की अवधि के होने के कारण आई जे एम ए के तर्क का कोई आधार नहीं है। टाइल्स मामले जिसमें जांच की अवधि बाद की अवधि के रूप में निर्धारित थी के बाद शुरू की गई और समाप्त की गई एन एस आर की पर्याप्त संख्या रही है। बाद की जांच की अवधि की प्रथा नियम 22 के प्रावधानों को देखते हुए सही है जो यह कहता है कि केंद्र सरकार इस नियमावली के उप नियम (1) में यथासंदर्भित समीक्षा की अवधि के दौरान ऐसे निर्यातकों अथवा उत्पादकों से आयातों पर अधिनियम की धारा 9क के उप धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्कों को नहीं लगायेगा और यदि नई शिपर को एन एस आर को आरंभ किये जाने के पूर्व निर्यात करना हो तब यह नियमावली व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं करेगी।
- xvi. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बाद की जांच की अवधि के कारण से आवेदक (क) केवल औपचारिक निर्यात करने अर्थात् 163 मी. ट. निर्यात (ख) कृत्रिम रूप से उच्च कीमत पर इस कीमत में हेर फेर करने और इसे गलत तरीके से पेश करने में सक्षम हुए हैं। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। यहां आवेदक ने संबद्ध वस्तु का लगभग 1100 – 1200 मी. ट. (और न कि 163 मी. ट. जैसा कि तर्क दिया गया है) का

निर्यात किया है जो बहुत अधिक मात्रा है और इस प्रकार की पर्याप्त मात्रा संभव नहीं हो सकती थी यदि कीमत में हेर फेर न किया गया होता जैसा कि आरोप लगाया गया है।

- xvii. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारत में निर्यात करने के लिए कोई प्रतिबंधता नहीं है यह दर्शाता है कि निर्यातक गंभीर नहीं है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का लगभग 1100 – 1200 मी. ट. निर्यात किया है जो बहुत अधिक मात्रा है।
- xviii. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एन एस आर समीक्षा में निर्यात विश्वसनीय वाणिज्यिक लेन देन होना चाहिए। यह नोट किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में नई शिपर ने अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने के लिए बहुत अधिक मात्रा का निर्यात किया है। यह हमारे अनुरोध के प्रति बिना किसी पक्षपात के है कि मेक्सिको – राइस मामले में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी है कि प्राधिकारी पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के तत्वाधान में नई शिपर समीक्षा आयोजित करने में मात्रा से संबंधित किसी आवश्यकताओं को अधिरोपित नहीं कर सकते हैं जो भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 का आधार है। हालांकि, वर्तमान मामले में निर्यातों की मात्रा निश्चित रूप से निर्यातों की तर्कसंगतता की जांच करने के लिए प्राधिकारी द्वारा लागू किये गये कुछ मानदंडों को पूरा करता है जैसा कि हाल के कुछ एन एस आर जांच परिणामों में स्पष्ट है।
- xix. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और आवेदकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। दोनों तर्कों का कोई आधार नहीं है। वर्तमान मामले में आयातक आवेदक के संबंधित पक्षकार नहीं हैं और किसी भी प्रकार से निर्यातक ने आयातक के प्रश्नावली के उत्तर को उन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य कर सकता था। आवेदक ने इस नियमावली में यथा अनुमत गोपनीयता का दावा किया है। वास्तव में इन पक्षकारों ने वास्तविक निर्यातों की सीमा भी दी है जिससे कि घरेलू उद्योग को वर्तमान मामले की बेहतर समझ हो सके।
- xx. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये हैं कि किस प्रकार से उनके द्वारा दावा किये गये निर्यात कीमत तर्कसंगत, विश्वसनीय है। इस तर्क का कोई कानूनी अथवा तथ्यात्मक आधार नहीं है। बात यह रह जाती है कि आवेदक ने भारत में बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया है जो अपने आप में कीमत की तर्कसंगतता को प्रमाणित करता है। ऐसा कोई निर्यात कृत्रिम रूप से बढ़ायी गई कीमत पर किया जाना संभव नहीं हो सकता था।
- xxi. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबंधित आयातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी इस सूचना का सत्यापन नहीं कर सकते हैं और अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं कि निर्यातक और आयातक के बीच कोई क्षतिपूर्ति संबंधी व्यवस्था नहीं है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहां आयातकों ने सहयोग नहीं किया लेकिन निर्यातकों द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत का सत्यापन किया गया था और स्वीकार किया गया था। आयातक द्वारा असहयोग किसी भी प्रकार से निर्यातक द्वारा दावा की गई कीमत की विश्वसनीयता को हानि नहीं पहुंचाती है और अन्य तंत्र हैं जिनका उपयोग उसका सत्यापन करने के लिए किया जा सकता है जैसे सीमा शुल्क/ डी जी सी आई एंड ए आदि के आंकड़े।
- xxii. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू बिक्री कीमत और विभिन्न प्रकार के उत्पादन की लागत दोनों के संबंध में संपूर्ण रूप से अपूर्ण सूचना प्रतीत होती है और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी के उत्पाद प्रकारों में अंतरों का उल्लेख करने के लिए रिकार्ड पर कोई सूचना है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में सभी लागू उत्पाद प्रकार से संबंधित सूचना है।
- xxiii. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बंगला देश के निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य और सूचना की मात्रा हमेशा से सभी पिछली जांचों में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। ऐसे अभिकथनों का कोई आधार

नहीं है। यह महसूस किया जाता है कि प्राधिकारी ऐसी जांच को शुरू करता है और उसे पूरा करता है जब ऐसी जांच के लिए मामला स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो और न केवल उसके बारे में आरोप लगाया गया हो।

ड. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है :

“22. निर्यातकों के लिए पाटन का मार्जिन जिसके लिए मूल रूप से जांच नहीं की गई।

- (1) यदि कोई उत्पाद पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन है तब निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रश्नगत निर्यात देश के किसी निर्यातकों अथवा उत्पादकों जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत में इस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक आवधिक समीक्षा करेगा बशर्ते कि ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाते हों कि वे निर्यातक देश जो इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन हैं, में इसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं।
- (2) केंद्र सरकार इस नियमावली के उपनियम (1) में यथा संदर्भित समीक्षा की अवधि के दौरान इस प्रकार के निर्यातकों अथवा उत्पादकों से आयातों पर इस अधिनियम की धारा 9(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क नहीं लगायेगा :

बशर्ते कि यदि प्राधिकारी इस प्रकार से सिफारिश करते हैं और यदि इस प्रकार की समीक्षा के फलस्वरूप इस प्रकार के उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता हो, केंद्र सरकार अनंतिम आकलन का सहारा ले सकती है और आयातक से गारंटी की मांग कर सकती है, यह समीक्षा के आरंभ होने की तिथि से ऐसे मामलों में स्पष्टगामी प्रभाव से शुल्क लगा सकती है।”

13. डब्ल्यू टी ओ के करार के अनुच्छेद 9.5 में नीचे दिए गए अनुसार उल्लेख किया गया है -

“9.5 यदि कोई उत्पाद किसी आयातक देश में पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन हों तब प्राधिकारी तत्परता से प्रश्नगत निर्यातक देश के किसी निर्यातकों अथवा उत्पादकों जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान आयातक देश को उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से समीक्षा करेगा बशर्ते कि यह निर्यातक अथवा उत्पादक ये दर्शा सकें कि वे निर्यातक देश जो इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन हैं, में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं। इस प्रकार की समीक्षा आयातक देश में सामान्य शुल्क के आकलन और समीक्षा की कार्यवाहियों की तुलना में बंधे हुए आधार पर आरंभ की जायेगी और पूरी की जायेगी। कोई पाटनरोधी शुल्क समीक्षा किए जाने के समय इस प्रकार के निर्यातकों अथवा उत्पादकों से आयातों पर नहीं लगाया जायेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी मूल्यांकन को रोक सकते हैं और/ अथवा गारंटी का अनुरोध कर सकते हैं कि यदि इस प्रकार की समीक्षा के फलस्वरूप इस प्रकार के उत्पादकों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता हो, पाटनरोधी शुल्क इस समीक्षा के आरंभ होने की तिथि के पूर्व के समय से लगाया जा सकता है।”

14. उपर्युक्त नियम, विश्व व्यापार संगठन के करार के प्रावधानों और डी जी टी आर की विगत प्रथा के संबंध में, एक नई शिपर समीक्षा जांच संबद्ध देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगता है के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के संबंध में अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित परिस्थितियों में की जानी है :

- i. यह कि निर्यातक अथवा उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है और
- ii. यह कि निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाते हैं कि वे निर्यातक देश जो संबंधित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन हैं, ने किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं।

15. वर्तमान मामले मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) और मैसर्स एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी (निर्यातक/ व्यापारी), यू एस ए ने संयुक्त रूप से "पटसन उत्पाद" पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाला/ केबल किया हुआ और एकल) और पटसन सेकिंग थैले" पर अलग अलग पाटन मार्जिन की मांग करते हुए प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और नई शिपर समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया है।
16. 'नई शिपर' के रूप में आवेदकों की पात्रता के संबंध में, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा किये गये दावों का विस्तृत परीक्षण जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े/ सूचना के संबंध में प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेजों का तालिका अध्ययन शामिल है, किया है। इस प्रकार की जांचों को नियम 22 की अपेक्षाओं और प्राधिकारी की विगत प्रथाओं को देखते हुए आयोजित की गई थी। किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने अनुरोधों को छोड़कर किसी ठोस साक्ष्यों के रूप में एन एस आर के लिए उत्पादक/ निर्यातक द्वारा शर्त को पूरा न किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक वर्तमान मामले में नई शिपर समीक्षा प्राप्त करने के पात्र हैं।

च. आवेदक के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण

i. आवेदक उत्पादक की जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद की समग्र बिक्री

17. उत्पादक/ निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद (यार्न और सेकिंग थैला) और गैर विचाराधीन उत्पाद (सेकिंग कपड़े) दोनोंका उत्पादन और बिक्री नीचे दिये गये अनुसार किया है :

	यार्न	सेकिंग थैले	सेकिंग कपड़ा
उत्पादन	***	***	***
कुल बिक्री	***	***	***
घरेलू बिक्री	***	***	***
भारत को बिक्री	***	***	-
तृतीय देशों को बिक्री	***	-	-

काउंट वार/ किस्म वार बिक्री का ब्यौरा नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र.सं.	पी सी एन	भारत			तृतीय देश			घरेलू		
		मात्रा (मी. ट.)	मूल्य (बी डी टी)	कीमत बी डी टी/ मी. ट.	मात्रा (मी. ट.)	मूल्य (बी डी टी)	कीमत बी डी टी/ मी. ट.	मात्रा (मी. ट.)	मूल्य (बी डी टी)	कीमत बी डी टी/ मी. ट.
	सी बी									
1	9 एलबीएस 1 पीएलवाई	***	***	***	-	-	-	-	-	-
2	9 एलबीएस 2 पीएलवाई	-	-	-	-	-	-	***	***	***
3	11 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
4	13 एलबीएस 1 पीएलवाई एवं 16 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-

	मिश्रित लॉट									
5	16 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
6	20 L एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	-	-	-	***	***	***
7	28 एलबीएस 6 पीएलवाई	-	-	-	-	-	-	***	***	***
	सी आर टी									
8	24 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
9	24 एलबीएस 1 पीएलवाई एवं 26 एलबीएस 1 पीएलवाई मिश्रित लॉट	-	-	-	***	***	***	-	-	-
	आयोधित वनस्पति तेल									
10	18 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
11	18 एलबीएस 1 पीएलवाई एवं 16 एलबीएस 1 पीएलवाई मिश्रित लॉट	-	-	-	***	***	***	-	-	-
	हैसियन									
12	9.5 एलबीएस 1 पीएलवाई	***	***	***	***	***	***	-	-	-
13	10 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
14	10 एलबीएस 2 पीएलवाई	***	***	***	-	-	-	-	-	-
15	11 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
16	12 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
17	13 एलबीएस 1 पीएलवाई	***	***	***	-	-	-	-	-	-
18	14 एलबीएस 1 पीएलवाई	***	***	***	-	-	-	***	***	***
19	14 एलबीएस 3 पीएलवाई	-	-	-	-	-	-	***	***	***
20	16 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
21	18 एलबीएस 2 पीएलवाई	***	***	***	-	-	-	-	-	-
22	21 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
23	24 एलबीएस 1 पीएलवाई	***	***	***	-	-	-	***	***	***
24	28 एलबीएस 1 पीएलवाई, 18 एलबीएस 1 पीएलवाई (मिश्रित लॉट)	-	-	-	***	***	***	-	-	-

	सेकिंग									
25	10 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	-	-	-	***	***	***
26	11 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
27	13 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
28	14 एलबीएस 1 पीएलवाई	***	***	***	-	-	-	-	-	-
29	16 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
30	16 एलबीएस 3 पीएलवाई	-	-	-	-	-	-	***	***	***
31	18 एलबीएस 2 पीएलवाई	***	***	***	-	-	-	***	***	***
32	20 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
33	24 एलबीएस 1 पीएलवाई	-	-	-	***	***	***	-	-	-
34	28 एलबीएस 1 पीएलवाई	***	***	***	***	***	***	-	-	-
35	28 एलबीएस 3 पीएलवाई	***	***	***	-	-	-	-	-	-
36	28 एलबीएस 1 पीएलवाई आशोधित वनस्पति तेल	-	-	-	-	-	-	***	***	***
37	सेकिंग थैले	***	***	***	-	-	-	***	***	***
	कुल योग	***	***	***	***	***	***	***	***	***

ii सामान्य मूल्य

18.

क. तालिका के अध्ययन के दौरान कंपनी ने प्रतिनिधियों ने जांच की अवधि के लिए कंपनी की प्रमुख कच्चे माल अर्थात् दैनिक आधार पर मानवीय रूप से तैयार किया गया पटसन खरीद पंजी, उत्पादन रिकार्डों अर्थात् बंगला देश जूट स्पिन्नर एसो. (बी जे एस ए) को प्रस्तुत मासिक उत्पादन रिपोर्ट, मूल्यवर्धित कर विवरणी प्रतियां, बिक्री रिकार्ड, लेखा परीक्षित लेखाओं से संबंधित अपने दावे के समर्थन में ब्यौरा दिया। प्रेक्टिस करने वाले सनदी लेखाकार प्रमाण पत्र दिनांक 15.07.2019 ने यह प्रमाणित किया कि जांच की अवधि के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित लेखाओं और अन्य लेखाओं/ वित्तीय रिकार्डों को रखा जा रहा है और उसकी सूचना बी एफ आर एस का पालन करते हुए आई सी ए बी द्वारा संदर्भित आई ए एस के अनुसार बंगला देश में आम तौर पर स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दी गई है। उत्पादकों/ निर्यातकों का मूल रिकार्ड कुल मिलाकर पेशेवर तरीके से व्यवस्थित नहीं रखा गया था और वह बंगला में भी था और उसका अनुवाद आवश्यक था। हालांकि जांच की अवधि की लेखा परीक्षित लेखाओं पर उत्पाद की लागत की गणना करने के लिए आधार के रूप में विचार किया गया है। कंपनी ने यार्न, सेकिंग कपड़े और सेकिंग थैले के लिए अलग अलग लेखांकन/ लागत रिकार्ड अनुरक्षित नहीं किया है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार/ काउंट के यार्न (अर्थात् सी बी, सी आर टी, सी आर टी और विभिन्न एल बी एस और काउंट के आशोधित वनस्पति तेल) सेकिंग कपड़े और सेकिंग थैले (विभिन्न एल बी एस और काउंट के) का उत्पादन कंपनी द्वारा किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के यार्नों और सेकिंग थैलों के बीच बिक्री कीमतों में अंतर है।

ख. जांच की अवधि के दौरान कंपनी ने *** मी. ट. यार्न, *** मी. ट. सेकिंग कपड़े और *** मी. ट. सेकिंग थैले का उत्पादन किया है। कच्चे माल की खपत को कंपनियों द्वारा सभी उत्पादों को मिलाकर बुक किया जाता है और विभिन्न प्रकार/ काउंट के यार्न, सेकिंग कपड़े और सेकिंग थैले के लिए कोई अलग रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। कच्चे माल का खपत मूल्य का आवंटन कंपनी द्वारा उत्पादन की मात्रा के आधार पर किया गया है। यूटिलिटी, पैकिंग सामग्री, उपभोग्य वस्तुओं, कर्मचारी लागत, ह्रास, मरम्मत और अनुरक्षण और अन्य निर्माण ऊपरी शीर्ष की लागतों का आवंटन कंपनी द्वारा उत्पादन मूल्य के आधार पर संबंधित उत्पाद के लिए किया गया है। वित्तीय लागत, अन्य प्रशासनिक ऊपरी शीर्ष और बिक्री ऊपरी शीर्ष का आवंटन बिक्री के मूल्य के आधार पर किया गया है। मैसर्स एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी (निर्यातक/ व्यापारी) के संबंध में प्रमाणित परिशिष्ट 5 के अनुसार वे लाभप्रद कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं और उस पर विचार किया गया है।

ग. यह कंपनी विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए अलग अलग रिकार्ड नहीं रख रही है हालांकि, यह देखते हुए कि उन उत्पादों जिनकी बिक्री अपेक्षाकृत अधिक कीमतों पर की जाती है, का भी अधिक लागत होगी, कच्चे माल की लागत का आवंटन उत्पादन की मात्रा, यूटिलिटी के आधार पर किया गया है और परिवर्तन लागत का आवंटन उत्पादन के मूल्य के आधार पर किया गया है और प्रशासनिक एवं वित्तीय लागत का आवंटन बिक्री मूल्य के आधार पर किया गया है। तदनुसार, सभी किस्मों के यार्न और सेकिंग थैले के उत्पादन की औसत लागत क्रमशः बी डी टी *** / मी. ट. और बी डी टी *** / मी. ट. के रूप में तय किया गया है।

घ. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल जांच में, यार्न के “सामान्य मूल्य” की गणना करने के लिए अपनी गई पद्धति यार्न की सभी किस्मों सहित भारित औसत आधार पर थी। मूल जांच ऐतिहासिक जांच की अवधि के आधार पर की गई थी और अनुकूल पाटन मार्जिन के लिए समायोजित की जा रही निर्यात कीमत के लिए अवसर उपलब्ध नहीं था जैसा कि नई शिपर समीक्षा में हो सकता था। इस कारण से भारित औसत दृष्टिकोण व्यापक तौर पर सांकेतिक होंगे। नई शिपर की समीक्षा होने के कारण वर्तमान मामला जिसमें भारत में निर्यात किये गये यार्न किस्मों की अलग अलग और कीमत है। उत्पादन का ग्रेडवार/ काउंट वार लागत एक महत्वपूर्ण मानदंड है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह देखते हुए कि यार्न की विभिन्न किस्मों के लिए कोई काउंट वार लागत उपलब्ध नहीं कराई गई है, यह संभव नहीं है कि विचाराधीन उत्पादन अर्थात् काउंट वार/ किस्म वार के आधार पर यार्न की लागत की गणना की जाये और जैसी भी स्थिति हो घरेलू अथवा उपयुक्त रूप से तीसरे देश के निर्यातों के लिए ओ सी टी जांच की जाये। इन विवस्थाओं के कारण प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान भारत में निर्यात किये गये विभिन्न किस्म के यार्न के लिए सामान्य मूल्य स्थापित करने में असमर्थ हैं। इन बाध्यताओं के अंतर्गत प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान भारत में निर्यात किये गये विभिन्न प्रकार के यार्नों के लिए सामान्य मूल्य स्थापित नहीं कर सके। प्राधिकारी ने आवेदक उत्पादक/ निर्यातक द्वारा की गई टिप्पणियों और बांग्लादेश उच्चायोग और घरेलू उद्योग द्वारा बाद के पैरा में प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोधों का उपयुक्त रूप से निपटारा किया है।

iii. निर्यात कीमत

19. प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि दिनांक 30 अगस्त, 2019 के प्रकटन में यह माना गया था कि उत्पादक/ निर्यातक ने एस एम पी इंटरनेशनल एल एल पी, यू एस ए के माध्यम से भारत में निर्यात किया है। उत्पादक / निर्यातक ने एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी, यू एस के के माध्यम से भारत में निर्यात किया है। यह नोट किया गया था कि शिपर एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी, यू एस ए ने कुछ मार्जिन रखने के बाद प्रत्येक खेप की बिक्री की है और उनकी निर्यात बिक्री लाभप्रद है। अतः कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत की गणना करने के लिए, शिपर को उत्पादक की बिक्री का संदर्भ लिया गया है। जांच की अवधि के दौरान, निर्यातक ने *** यू एस डालर (*** यू एस डालर/ मी. ट.) (सी एनल एफ) (ई आर *** बी डी टी/ डालर) के बीजक मूल्य पर *** मी. ट. की कुल 36 खेपों का निर्यात किया है। इन समायोजन का दावा अंतर्देशीय भाड़े पोर्ट पर खर्च और बैंक शुल्कों पर हुए वास्तविक खर्च के

आधार पर किया गा है। उपर्युक्त के आधार पर पटसन यार्न (सभी किस्मों) और सेकिंग थैले के लिए अलग अलग रूप में भारत में औसत निर्यात कीमत क्रमशः *** और *** है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादक/ निर्यातक ने *** मी. ट. यार्न का निर्यात किया है जिसमें भारत में जांच की अवधि के दौरान सी बी, हैसियन और सेकिंग किस्म और *** मी. ट. सेकिंग थैले शामिल हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसका व्यापक रूप से सह-संबंध डी जी - सिस्टम के आंकड़ों से है। आवेदक निर्यातक द्वारा यार्न और सेकिंग थैले का निर्यात बंगला देश से कुल आयातों का क्रमशः 2-3 प्रतिशत और 0-1 प्रतिशत है।

प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच करने के लिए बंगला देश से अन्य निर्यातकों के साथ आवेदक द्वारा भारत में जांच की अवधि के दौरान संभव सीमा तक नमूना आधार पर यार्न की विभिन्न किस्मों के निर्यात की कीमतों की तुलना की है कि क्या आवेदक निर्यातक के यार्न की विभिन्न किस्मों की निर्यात कीमतें वास्तविक थीं। दो विशिष्ट प्रकारों अर्थात् ग्रेड 14/1 और 28/1 के आवेदक निर्यातक की सेकिंग किस्मों की निर्यात कीमत की तुलना अन्य निर्यातकों (आवेदक के कुल निर्यात का 50-60 प्रतिशत है) करने पर यह नोट किया जाता है कि आवेदक निर्यातक की निर्यात कीमतें इन दो विशिष्ट श्रेणियों (औसत आधार पर 15-20 प्रतिशत) क्रमशः *** प्रतिशत और *** प्रतिशत अधिक है। अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लिए इस प्रकार की तुलना के लिए तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है दो श्रेणियों की तुलना करने पर प्राधिकारी इसे उपयुक्त नहीं मानते हैं कि आवेदक निर्यातक की निर्यात कीमत को विश्वसनीय माना जाये। अन्य विचाराधीन उत्पाद प्रकार अर्थात् सेकिंग थैले क्योंकि इसकी मात्रा बंगला देश से सेकिंग थैले के कुल आयातों का केवल 0-1 प्रतिशत है के संबंध में, भारत में सेकिंग थैले की विश्वसनीय निर्यात कीमत सिद्ध करने के लिए इसे पर्याप्त के रूप में नहीं माना जा सकता है। निर्यात कीमत और घरेलू उद्योग के विचार से आवेदक उत्पादक/ निर्यातक के प्रकटन पश्चात् अनुरोधों का निपटारा बाद के पैराओं में उपयुक्त रूप से किया गया है।

iv. पाटन मार्जिन

20. प्राधिकारी उपर्युक्त (iii) और (ii) को देखते हुए इस जांच के अधीन विचाराधीन उत्पाद के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन स्थापित करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, प्राधिकारी ये नोट करते हैं कि आवेदक उत्पादक ने समग्र आधार पर उत्पादन की लागत उपलब्ध कराई है। यदि भारत में निर्यात किये गये यार्न की सभी किस्मों के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत 5 प्रतिशत के उपयुक्त लाभ के साथ और (उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित कीमत अंतर को देखते हुए उपयुक्त रूप से समायोजित) की निर्यात कीमत की तुलना की जाये तब मूल जांच में नमूने न लिये गये उत्पादकों/ निर्यातकों पर लागू की गई शुल्क की सीमा में पाटन स्पष्ट होगा। भारत में सेकिंग थैले की निर्यात मात्रा विश्वसनीय निर्यात कीमत स्थापित करने के लिए बहुत नगण्य है। प्राधिकारी अंतिम निर्धारण में इन पहलुओं पर उपयुक्त रूप से विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। प्राधिकारी ने आवेदक उत्पादक/ निर्यातक द्वारा तथा घरेलू उद्योग द्वारा भी आवेदक उत्पादक/ निर्यातक को अलग अलग पाटन मार्जिन देने पर प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों को बाद के पैराओं में उपयुक्त रूप से निपटारा किया गया है।

छ. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

21. घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स टी पी एम ने प्रकटन पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :

- एन एस आर जांच में यह दर्शाया जाने की आवश्यकता है कि नई शिप्पर समीक्षा मामले में जांच की अवधि के दौरान नई शिप्पर आवेदक द्वारा किया गया निर्यात वास्तविक वाणिज्यिक लेन देन है जिसे पाटन मार्जिन के लिए आधार होना है। "उद्देश्य खरीद बिक्री के लिए वस्तु" के उचित मूल्य का पता लगाना नहीं था बल्कि इसकी वाणिज्यिक तर्कसंगतता के लिए प्रत्येक बिक्री की जांच करना था।
- आयात की मात्रा कुल आयात की मामूली मात्रा है। इसके अलावा, निर्यातक को निर्यात की मात्रा के संबंध में निर्यात कीमत की उपयुक्तता और विश्वसनीयता को स्थापित करना ही चाहिए। प्राधिकारी द्वारा की गई जांच में यह दर्शाया है कि निर्यात की कीमत प्रतिनिधिक नहीं है।

- iii. निर्यातक द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई वास्तविक अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध कराया गया कारण नहीं है कि किस प्रकार से निर्यातक अन्य को छोड़कर अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर उस स्थिति में वस्तुओं का निर्यात करने में सक्षम हो पाये हैं जब उसी प्रकार की वस्तु का आयात अपेक्षाकृत बहुत कम कीमत पर किया जा रहा है।
- iv. अन्य मानदंडों जिनकी जांच निर्यात कीमत की उपयुक्तता जैसे उस कीमत पर जिस कीमत पर घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है, की जानी चाहिए यदि निर्यातक अलग अलग पक्षकारों के लिए कीमतों में अंतरों, आयातक और इसके क्रेता तथा निर्यातक एवं आयातक की कीमत जिस पर इन वस्तुओं की फिर से बिक्री आयातक आदि द्वारा की गई है, के बीच क्षतिपूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं का आभाव के कारणों को दर्शाता हो।
- v. आवेदकों ने भारत में आयातक से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। भारत में आयातक इस जांच में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। आयातकों से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त न होने को देखते हुए, आवेदक ने यह स्थापित नहीं किया है कि इस प्रकार से निर्दिष्ट प्राधिकारी आयात कीमत की उपयुक्तता का पता लगा सकता है।
- vi. आवेदकों ने ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया है जिससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि आवेदकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह दर्शाया है कि वे नियम 22 के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है।

22. निर्यातक/ उत्पादक प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स एम एस पोथल एंड एसो. ने प्रकटन पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :

क. आवेदक द्वारा उत्पादन किये गये विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में लागत को अस्वीकार करने के लिए आधारों पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता क्योंकि इसे अस्वीकार करना न्यायोचित और निष्पक्ष नहीं है।

- i. उत्पादक अथवा निर्यातक द्वारा निर्यात किये गये किसी वस्तु के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण का कानूनी ढांचा धारा 9क (6क) और नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है जिससे कि अनुबंध 1 को लागू करते हुए नियम 10 के अंतर्गत की प्रक्रिया को बनाया गया है।

“निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन का मार्जिन का निर्धारण करते समय अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करेंगे -

1. *सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में उल्लिखित लागतों के कारकों का निर्धारण सामान्य तौर पर जांच के अधीन निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गये रिकार्डों के आधार पर किया जायेगा बतर्हि इस प्रकार का रिकार्ड निर्यात करने वाले देश के सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हों और इस प्रकार का रिकार्ड तर्कसंगत रूप से विचाराधीन वस्तु के उत्पादन और बिक्री से संबद्ध लागत को दर्शाता हो।” (बल दिया गया)*
- ii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 का उपर्युक्त पाठ का स्पष्ट रूप से आधार विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.2.1.1 में है। अनुच्छेद 2.2.1.1 की आवश्यकताओं का उल्लेख करते समय, मिस्त्र – स्टील रेबर ने विश्व व्यापार संगठन के पैनल में नोट किया कि अनुच्छेद 2.2.1.1 और 2.2.2 दोनों दो कारकों पर बल देते हैं, पहला कारक यह है कि उत्पादन की लागत की गणना तब तक प्रश्नगत कंपनी द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है, वास्तविक लेखा बही और रिकार्ड के आधार पर गणना की जानी है परंतु दूसरा कारक यह है कि शामिल की जाने वाली लागत वे हैं जो तर्कसंगत तरीके से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबद्ध लागतों को दर्शाते हों।

- iii. वर्तमान जांच में, आवेदक ने कंपनी द्वारा रखे गये रिकार्डों जो जी ए ए पी के अनुसार है विचाराधीन उत्पाद से संबंधित लागत सूचना प्रस्तुत की है। कंपनी के पास विभिन्न किस्मों के यार्न के लिए काउंटवार लागत रखने की कोई पद्धति नहीं है क्योंकि इस प्रकार के लागत निर्धारण व्यापार की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं। प्रकटन विवरण के पैरा 17. ख. में यह स्वीकार किया गया है कि आयोजक विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र प्रकार का उत्पादक है जो पटसन यार्न है और उसकी लागत उपलब्ध थी। प्रकटन विवरण जिसे ऊपरोक्त में फिर से दिया गया है में पैरा 17. ग. में कहीं भी यह नहीं कहता है कि आवेदक यह दर्शाने में सफल नहीं रहे हैं कि इनका लागत रिकार्ड जी ए ए पी के अनुसार रखा जाता है और लागत का कोई कारक विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध लागत को नहीं दर्शाता है जो लागत के किसी विशेष कारक के संबंध में यार्न (पटसन उत्पाद) है। इसके अलावा, कृपया यह नोट करें कि कंपनी तीन किस्मों के यार्न अर्थात् सी बी, हैसियन और सेकिंग का उत्पादन करता है और इन तीन किस्मों में प्रत्येक तीन किस्मों में काउंट काफी संख्या में हैं और काउंटों में प्लाई की संख्या है, और इस कारण से लघु कंपनी के लिए यह व्यवहार्य नहीं होगा कि वह पी सी एन के प्रत्येक के लिए प्रकारवार कच्चे माल की लागत बनाये रखे। टिप्पणी केवल यह है कि काउंटवार/ किस्मवार के आधार पर अलग अलग प्रकार के यार्न के उत्पादन की लागत की गणना करना संभव नहीं है क्योंकि काउंटवार निर्धारण नहीं दिया गया है। यह विचाराधीन उत्पाद के संबंध में लागत को अस्वीकार करने के लिए एक निष्पक्ष आधार नहीं हो सकता है।
- iv. चूंकि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के लिये लागत उपलब्ध कराई है जो यहां यार्न है, यह टिप्पणी की विचाराधीन उत्पाद के लिये संगत लागत उपलब्ध नहीं है, पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है यद्यपि प्रकटन विवरण में बाद के हिस्से में प्राधिकारी ने यह नोट किया कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के लिये भारित औसत लागत उपलब्ध कराई है। जहां तक विभिन्न किस्मों के यार्न का संबंध है, आवेदक ने सुझाव दिया कि मुख्य लागत कच्चे मालों के आधार पर है और कच्चे माल की लागत का आवंटन विभिन्न प्रकारों के यार्न के संबंध में विक्री मूल्य अनुपात के आधार पर किया गया है। यह उस सिद्धांत के आधार पर है कि उत्पाद जिससे बाजार में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्ति होती है, का अधिक लागत भी होती है। इस प्रकार की पद्धति तर्कसंगत है और इससे प्राधिकारी यार्न के प्रकारवार लागत का भी निर्धारण करने में सक्षम हो सकते थे यद्यपि नियम की अपेक्षा विचाराधीन उत्पाद के लिए लागत और न कि इसके परस्पर प्रकारों के लिए लागत निर्धारण करना है। बिना पक्षपात के, उपर्युक्त आधार पर यार्न का प्रकारवार लागत संलग्न है।
- v. प्रकारवार लागत के संदर्भ में आवेदक यह भी अनुरोध करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार का अनुबंध II स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति का समाधान करता है जहां दी गई सूचना अनुबंध II के पैरा 5 में सभी दृष्टिकोणों से आदर्शजनक नहीं हो सकते हैं। प्रकारवार लागत के अभाव को इस संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। यह करार स्पष्ट रूप से कहता है कि यद्यपि दी गई सूचना सभी दृष्टिकोणों से आदर्शजनक नहीं हो सकते हैं, यह प्राधिकारियों को इसके संबंध में नहीं मानने से न्यायोचित नहीं ठहराना चाहिए बतर्से हितवद्ध पक्षकार ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य किया हो। वर्तमान मामले में आवेदक ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य किया है क्योंकि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के स्तर पर अपने रिकार्डों के अनुसार लागत उपलब्ध कराई है और इसके साथ ही उचित आवंटन आधार पर प्रकारवार लागत उपलब्ध कराई है। प्रकारवार आधार पर लागत का निर्धारण आवंटन का एक मामला हो सकता है और उसके लिए एक व्यवहारिक तथा सामान्य रूप से अपनाई गई पद्धति का भी सुझाव दिया गया था।
- vi. उपर्युक्त के बावजूद, विवादास्पद प्रश्न जो पैरा 17. ग. में प्राधिकारी की टिप्पणी से निकलता है यह है कि क्या प्राधिकारी इस महत्वपूर्ण कारण से नई शिप्पर समीक्षा में सामान्य मूल्य के संदर्भ में जांच के अधीन वस्तु की लागत के निर्धारण में अलग दृष्टिकोण अपना सकते हैं कि वर्तमान एन एस आर की जांच की अवधि बाद की अवधि है जिसके बारे में आवेदक को निर्यात के समय जानकारी है अथवा प्रश्नगत जांच एक नई शिप्पर समीक्षा है? हमारा सादर अनुरोध है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण कि कोई कानूनी सूचिता नहीं है और अनुबंध II में दी गई पद्धतियां पाटन मार्जिन के प्रत्येक निर्धारण में लागू है, चाहे वह एक नई जांच हो अथवा नई शिप्पर समीक्षा हो। इसके साथ ही जांच की प्रकृति जो अपने आप में यहां एन एस आर है किसी भी प्रकार से लागत की तर्कसंगतता को हानि नहीं पहुंचाती है और न ही पक्षपात करता है और न ही जांच

की प्रकृति लागत की तर्कसंगतता का निर्धारण करने के लिए अपने आप में लागत का खंडन करने के लिए एक आधार हो सकता है। समीक्षा की प्रकृति लागत की तर्कसंगतता का निर्धारण करने के लिए अपने आप में एक आधार नहीं हो सकता है और लागत की तर्कसंगतता की जांच आवेदक के दावों में शामिल की गई लागत के विभिन्न कारकों की तर्कसंगतता के आधार पर की जानी है और यह जांच की प्रकृति का उल्लेख करते हुए पूर्वानुमान आधार पर भी नहीं हो सकता है। यह आदरपूर्वक अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 में की गई परिकल्पना के अनुसार नई शिप्पर समीक्षा के उद्देश्य के विरुद्ध जाता है और इस प्रकार का दृष्टिकोण गंभीर रूप से आवेदक के अधिकारों को हानि पहुंचा सकता है और वर्तमान मामले में बाद की जांच की अवधि का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कानून के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार किया गया था। जैसे ही जांच की अवधि का निर्धारण कानून में दी गई अनुमति के अनुसार किया जाता है, वह आवेदक द्वारा दावा किये गये लागत और कीमत की विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए आधार नहीं हो सकता है और इस प्रकार का पूर्वानुमान वर्तमान जांच शुरुआत के आकलनों के विरुद्ध जाता है। यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध में परिकल्पना किये गये सिद्धांतों अर्थात् किसी पाटनरोधी जांच जैसे सामान्य मूल्य के संदर्भ में लागत के निर्धारण के आधार पर किया जाये और एक एन एस आर आवेदक को उसकी लागत का निर्धारण करते समय अलग स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए।

- vii. यह भी अनुरोध किया जाता है कि कानून के अंतर्गत अपेक्षा विचाराधीन उत्पाद के लिये और न कि प्रकारवार के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करना है और उस संदर्भ में, विचाराधीन उत्पाद की लागत को नहीं मानना जो जी ए ए पी के आधार पर कंपनी द्वारा रखे गये रिकार्डों के अनुसार है बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। ई सी - बेड लिनन में, विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने निम्नलिखित पाया :

“53. हम पाटनरोधी करार के आर्टिकल 2.4.2 अथवा किसी अन्य प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं जो जांच के अधीन उत्पादों के प्रकारों अथवा मॉडलों के लिए ‘पाटन के मार्जिन के होने’ को सिद्ध करने के लिए प्रावधान करता हो; इसके विपरीत ‘पाटन के मार्जिन के होने’ को सिद्ध करने के लिए सभी संदर्भ उस उत्पाद के लिये संदर्भ हैं जो जांच का विषय है। उसी प्रकार से हम इस धारणा का समर्थन करने के लिए अनुच्छेद 2.4.2 में ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं कि पाटनरोधी जांच में दो अलग अलग चरणों की परिकल्पना अथवा उसमें अंतर पाटनरोधी करार के इस प्रावधान द्वारा किसी भी रूप में किया गया है और न ही यूरोपीय समुदायों द्वारा अंतरों को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई तर्क इन दो चरणों के आधार पर उसी उत्पाद के प्रकारों अथवा मॉडलों के बीच किया जा सकता है। जिसकी भी पद्धति का उपयोग पाटन के मार्जिन की गणना करने के लिए की गई थी, हमारे दृष्टिकोण से इन मार्जिनों को संपूर्ण रूप में जांच के अधीन उत्पाद के लिए स्थापित किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। हम यूरोपीय समुदायों से सहमत होने की स्थिति में नहीं है कि अनुच्छेद 2.4.2 में ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है कि किस प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन के समय मार्जिन की गणना की जाये।” (बल दिया गया है)

- viii. इस प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के परस्पर प्रकारों के लिए आवेदक द्वारा रखे गये प्रकारवार/ काउंटवार लागत का न होना आवेदक द्वारा रखे गये अनुसार विचाराधीन उत्पाद की लागत को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। अगर आवेदक दो प्रमुख अपेक्षाओं अर्थात् जी ए ए पी के अनुसार रिकार्ड तथा लागत की तर्कसंगतता जिसका प्रावधान इस नियम में किया गया है, के अनुसार विचाराधीन उत्पादों की लागत प्रस्तुत नहीं किया होता तब यह एक अलग मामला हुआ होता। वर्तमान मामले में, आवेदक ने नियमावली के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराये हैं और उसमें दिये गये आधारों के लिए लागत को अस्वीकार करना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और हम प्राधिकारी के समक्ष यह प्रार्थना करते हैं कि वे न्याय और निष्पक्षता के हित में इस पर फिर से विचार करें।

- ख. आवेदक द्वारा किये गये दावे के अनुसार निर्यात कीमत को अस्वीकार करने के लिए आधारों पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि अस्वीकार करना न्यायोचित और निष्पक्ष नहीं है।**
- i. प्राथमिक अनुरोध के रूप में, यह दोहराया जाता है कि आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा का निर्यात किया है और इस प्रकार का कोई मात्रा का स्तर उस कीमत पर संभव नहीं हो सकता था जो प्रचलित बाजार कीमत की तुलना में अतर्कसंगत रूप से अधिक हो। आवेदक ने प्रचलित बाजार कीमतों से तुलनीय कीमत पर निर्यात किया है और यह किसी भी प्रकार से बढ़ाई गई कीमत पर नहीं था।
 - ii. आवेदक की निर्यात कीमत की तुलना अन्य निर्यातकों द्वारा किये गये कुछ निर्यातों का नमूने के रूप में एक निष्पक्ष पद्धति आवेदक की निर्यात कीमत की विश्वसनीयता की जांच करने के लिये नहीं है क्योंकि चयनित किया गया नमूना व्यापार के स्तर और मात्रा के मामले में बिल्कुल भी द्योतक नहीं है। आवेदक ने दिनांक 1.9.2019 के अपने पत्र के माध्यम से उचित तुलना के लिए बंगलादेश से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के समग्र आंकड़ों के लिए अनुरोध किया परंतु वह उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार की कोई तुलना तर्कसंगत आधार पर होनी है और चयनित किया गया नमूना बहुत कम है। जब तक और यदि आवेदक की निर्यात कीमत की तुलना अन्य निर्यातकों द्वारा की गई जांच की अवधि के दौरान भारत में बंगलादेश से विचाराधीन उत्पाद के उसी प्रकार के कुल निर्यात का एक बहुत बड़े हिस्से से नहीं किया जाता है तब इस दृष्टिकोण में किसी प्रकार का विपथन किये बिना कोई निष्पक्ष दृष्टिकोण पर नहीं पहुंचा जा सकता है।
 - iii. निर्यात कीमत जैसा कि सहयोगी नमूने में प्राधिकारी द्वारा विश्वास किया गया है सी आई एफ स्तर पर किया गया प्रतीत होता है और न कि पहुंच स्तर पर किया गया प्रतीत होता है। विचाराधीन उत्पाद पर अधिकांश निर्यातकों के लिए पाटनरोधी शुल्क लग रहा है और कोई भी कीमत की तुलना इस प्रकार के शुल्क पर विचार करते हुए किये जाने की आवश्यकता है। आवेदक ने वर्तमान समीक्षा के अध्यधीन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है और कोई भी पाटनरोधी शुल्क आयातों के समय इस प्रकार के विचाराधीन उत्पाद पर लागू नहीं था। इस प्रकार से, निर्यातक की शेष श्रेणी ने किसी निर्यातक से आयात करते हुए किसी आयातक की आयात कीमत जिस पर न्यूनतम शुल्क और किसी शुल्क के निर्यातक की तुलना उसी आधार पर नहीं की जा सकती है। शुल्क का कारक स्पष्ट रूप से आयातक के अंत में उस कीमत पर होता है और कोई भी तुलना यह देखने के लिए पहुंच स्तर पर की जानी होती है कि क्या आयातों की वास्तविक किसी थी। इस कारण से यह टिप्पणी की आवेदक की कीमत 15-20 प्रतिशत अधिक थी और इस कारण से यह विश्वसनीय नहीं है पर व्यापार के तथ्यों के आधार पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है।
 - iv. यहां यह भी नोट किया जाना है कि आवेदक ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया। जांच की अवधि की बाद की अवधि के निर्यातों का पाटन मार्जिन के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान कीमत भी इस प्रकार के कीमत स्तर को दर्शाती है जिसकी तुलना जांच की अवधि में कीमतों से की जा सकती है। कृपया यह भी नोट किया जाये कि कंपनी ने जांच की अवधि की बाद की अवधि में बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया है जो कीमत की विश्वसनीयता और निरंतरता को भी दर्शाता है। हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे जांच की अवधि के लिए आवेदक द्वारा दावा किये गये निर्यात कीमत की सत्यता की जांच करने के लिए भी निर्यात की जांच की अवधि के बाद की अवधि की कीमत पर विचार करें। जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान कीमत स्पष्ट रूप से यह दर्शायेगा कि अपेक्षाकृत कम मार्जिन प्राप्त करने के लिए कीमत को बढ़ाने के संबंध में निर्यातक का आरोप पूर्ण रूप से निराधार है।
 - v. इसके अलावा हम बंगलादेश जूट मिल्स कारपोरेशन द्वारा जारी किये गये एक परिपत्र को संलग्न कर रहे हैं जिसमें यह देखा जा सकता है कि सी बी 10 एल बी एस/ 1 प्लाई के लिये कीमत अंतर्राष्ट्रीय निर्यात कीमत के अनुसार *** यू एस डॉलर प्रति मी. ट. के रूप में सूचीबद्ध है। जांच की अवधि के दौरान हमारी कीमत बी डी टी *** थी जो यू एस डॉलर *** प्रति मी. ट. के बराबर है। यह देखा जा सकता है कि हमारी कीमत की तुलना सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से की जा सकती है। इस परिपत्र की संगतता यह है कि यद्यपि इस प्रकार कीमतें बेंचमार्क के रूप में कठोरतापूर्वक बाध्यकारी नहीं हैं फिर भी इस प्रकार की कीमतों में स्पष्ट रूप से बाजार में प्रचलित कीमत सीमा को दर्शाया और आवेदक ने भारत में इस प्रकार की अधिसूचित

कीमत से तुलनीय वास्तविक कीमत पर निर्यात किया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक ने उस यथार्थ कीमत पर निर्यात किया जो अन्य निर्यातकों द्वारा निर्धारित कीमत के समतुल्य है जिस पर विचार किया जा रहा था।

- vi. इसके अलावा हम बंगलादेश जूट गुड्स एक्सपोर्टर एसो. द्वारा जारी किये गये एक पत्र को संलग्न कर रहे हैं जिसमें उन्होंने 14/1 और 28/1 सेकिंग कोटि के यानों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का खुलासा किया है, यह कीमत जांच की अवधि के दौरान हमारी निर्यात कीमत से भी मिलता जुलता है। यह उस तथ्य का भी संकेत देता है कि आवेदक भारत में किसी कृत्रिम कीमतों पर निर्यात नहीं कर रहा था और इस प्रकार की कीमतें बाजार से बातचीत में बहुत प्रचलित थीं।
 - vii. इस प्रकार से उपर्युक्त के आधार पर यह अनुरोध किया जाता है कि प्रकटन विवरण में किये गये प्रस्ताव के अनुसार आवेदक द्वारा दावा किये गये निर्यात कीमत पर प्राधिकारी के दृष्टिकोण पर तथ्यों के आधार पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है और हम उसके लिए न्याय और निष्पक्षता के हित में प्रार्थना करते हैं।
- ग. आवेदक भारत में अपने निर्यातों के मामले में अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध करा सकते थे। किसी वैकल्पिक पद्धति के लिए किसी प्रस्ताव को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए।**
- i. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 जो नई शिप्पर समीक्षाओं को शासित करता है स्पष्ट रूप से यह कहता है कि *निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी निर्यातकों अथवा उत्पादकों के लिए पाटन से अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक आवधिक समीक्षा करेगा।* यह अपेक्षा अलग अलग पाटन मार्जिन का स्पष्ट रूप से निर्धारण है और यह कुछ अन्य पक्षकारों के लिए अथवा विगत में निर्धारित की गई कुछ अलग मार्जिन का अनुकूलन नहीं हो सकता है।
 - ii. यह भी आदरपूर्वक अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी उसी विचाराधीन उत्पाद के संबंध में जनता जूट मिल्स एन एस आर मामले के संबंध में हाल के एक एन एस आर में नमूने न लिये गये श्रेणी के लिए मार्जिन के आधार पर अलग मार्जिन का निर्धारण किया था। हालांकि, प्राधिकारी ने नीचे दिये गये अनुसार मेलामाइन के संबंध में एक अंतिम जांच की प्रक्रिया में उक्त निर्धारण पर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया *“प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस निर्धारण में प्राधिकारी ने निर्यात कीमत की तर्कसंगतता और विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया था और इस मामले के तथ्यों से बाध्य होकर आवेदक को पाटनरोधी शुल्क के नमूने न लिये गये श्रेणी देने का ही निर्णय लिया था”*।
 - iii. इस प्रकार से जनता जूट मिल मामले में नमूने न लिये गये श्रेणी के लिए मार्जिन का अनुकूलन उक्त मामले में कुछ वास्तविक बाध्यताओं का परिणाम था और वर्तमान मामले में इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक ने अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए ब्यौरा उपलब्ध कराया है और आवेदक द्वारा ये निर्यात जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक थे। कुछ अन्य मामलों में कुछ बाध्यकारी परिदृश्यों में लिया गया कोई दृष्टिकोण एक नियम विशेषकर नियम 22 में दी गई स्पष्ट कानूनी स्थिति को देखते हुए नहीं हो सकता है जिसमें प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह उनके संगत आंकड़ों के आधार पर नई शिप्परो के लिए अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करें। न ही नियम अथवा न ही पाटनरोधी करार में ऐसा कोई प्रावधान है जो प्राधिकारी को मूल मामले में निर्यातकों के नमूने न लिये गये श्रेणी के मार्जिन के अनुसार अपने निजी आंकड़ों के आधार पर अलग अलग मार्जिन अपनाने को छोड़कर एन एस आर आवेदक के लिए मार्जिन का अपनाये।
 - iv. बिना किसी पक्षपात के यह हमारा सादर अनुरोध है कि प्राधिकारी आवेदक के लिए अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने की स्थिति में होंगे और इन टिप्पणियों पर उचित तरीके से विचार किये जाने के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना को अपनाना अथवा किसी अन्य आधार को अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो जांच करने वाले प्राधिकारियों को केवल इस प्रकार के मामलों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण करने की

अनुमति देता है जहां कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्राप्त किये जाने से इनकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराता है और पर्याप्त रूप से जांच में बाधा पहुंचता है। उपर्युक्त परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति एन एस आर आवेदक पर लागू नहीं होती है क्योंकि आवेदक ने पूर्ण रूप से प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है और कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक था जिसे प्राधिकारी द्वारा मांगा जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित निर्णय इस संबंध में संगत हैं :

- क. अर्जेंटीना – सेरामिक टाइल्स में, पैनल ने यह माना कि “हमें यह स्पष्ट है और दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि जांच करने वाला कोई प्राधिकारी प्राथमिक स्रोत से सूचना नहीं मान सकता है और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 और अनुबंध II की विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत ही उपलब्ध तथ्यों का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार से जांच करने वाला कोई प्राधिकार केवल वही उपलब्ध तथ्यों का सहारा ले सकता है जहां कोई पक्षकार : (i) आवश्यक सूचना प्राप्त किये जाने से इनकार करता है; (ii) अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना नहीं दे पाता है; अथवा (iii) जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है।”
- ख. यू एस – स्टील प्लेट में, पैनल ने परिसीमन की सीमा का विश्लेषण किया है जो अनुबंध II का अनुच्छेद 3 जांच करने वाले प्राधिकारियों का अधिकार दी गई सूचना को अस्वीकार करने के लिए देता है और उसके बदले में उपलब्ध तथ्यों का सहारा लेने का अधिकार देता है और संयुक्त राज्य की स्थिति को स्वीकार नहीं किया कि अनुच्छेद 6.8 में ‘सूचना’ का आशय उन सभी सूचनाओं से है जो सदस्यों को उस मामले में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाओं को अस्वीकार करने का अधिकार देता है जहां कुछ आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- ग. ई सी – सालमॉन (नार्वे) में पैनल को यू एस – हॉट-रोल्ड स्टील से समर्थन मिला और यू एस – स्टील प्लेट ने यह माना कि “अनुबंध II का पैरा 3 जांच करने वाले प्राधिकारियों को उस स्थिति में अपने निर्धारणों के उद्देश्य से सभी प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार करने का निदेश देता है जब यह (i) ‘सत्यापन के लायक’; (ii) ‘उपयुक्त रूप से यह अनुरोध किया गया जिससे इसका उपयोग बिना किसी अनुचित कठिनाइयों के जांच में किया जा सकता है’; (iii) ‘समयबद्ध रूप में आपूर्ति की गई है’; और जहां लागू हो, (iv) ‘प्राधिकारियों द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार उस माध्यम में अथवा कंप्यूटर की भाषा में दी गई हो’। इस प्रकार से अनुबंध II का पैरा 3 जांच करने वाले प्राधिकारियों से यह आग्रह करता है कि वे सभी सूचनाएं जो तीन अथवा कभी की चार संचयी स्थितियों का निर्धारण करते समय पूरा करता हो, पर विचार करें। इसके बाद ऐसा होता है कि जहां सभी शर्तों को पूरा कर लिया गया हो, जांच करने वाला प्राधिकार निर्धारण करते समय प्रस्तुत की गई सूचना को अस्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।”

23. बंगलादेश उच्चायोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकटन के संबंध में टिप्पणियां

- i. संबंधित तीन कंपनियों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के निर्धारित प्रपत्र में और समयबद्ध रूप में जांच की अवधि के लिए भारत में तथा अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत और बंगलादेश में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य से संबंधित सभी संगत सूचनाएं प्रस्तुत कीं। उन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया और अलग अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई।
- ii. सभी संगत सूचनाओं को प्रस्तुत करने और पूर्ण सहयोग के बावजूद प्रकटन विवरण हमारी कंपनी के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों का निर्धारण नहीं करने का प्रस्ताव करता है। प्रकटन विवरण का अवलोकन यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि उत्पादक/ निर्यातक के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों के संबंध में सूचना मौलिक कारण से विश्वसनीय नहीं है कि जांच की जांच की अवधि बाद की अवधि थी और आवेदक को जांच की अवधि के बारे में जानकारी थी यद्यपि हमने कंपनियों द्वारा रखे गये अनुसार सत्यापन योग्य आंकड़े प्रस्तुत किये। नई शिप्पर समीक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूर्व की

जांचों में शेष दण्डात्मक शुल्क के अधिधीन नई शिप्पर को लाना नहीं था और पाटन के अलग अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्धारित जांच की अवधि में इनके कीमत संबंधी व्यवहार को प्रमाणित करने के लिए एक अवसर प्रदान करना है। इस कारण से यह बहुत अनुचित नहीं होगा कि उत्पादक/ निर्यातक के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को इस आधार पर नहीं माना जाये कि यह जांच बाद की अवधि में किया गया था।

- iii. आवेदकों ने “पटसन उत्पादों” का सत्यापन योग्य लागत प्रस्तुत किया है जो उत्पाद था और जिसके संबंध में सनदी लेखाकार ने दिनांक 15.07.2019 के अपने प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रमाणित किया कि जांच की अवधि के लिये कंपनी की लेखा परीक्षित लेखा और अन्य लेखा/ वित्तीय रिकार्ड निम्नलिखित बी एफ आर एस में आई सी ए वी द्वारा संदर्भित आई ए एस के अनुसार बंगलादेश में सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रखा जाता है और उसकी सूचना दी जाती है। चूंकि उत्पादक और निर्यातक ऐतिहासिक रूप से अपने आंकड़ों को किसी विशेष तरीके से रखते हैं अतः वे केवल इस जांच के लिए अपने लेखांकन पद्धतियों को नहीं बदल सकते थे। आवेदकों द्वारा रखे गये रिकार्ड इस प्रकार के प्रकारवार लागत निर्धारण का पालन नहीं करते हैं और इस प्रकार का प्रकारवार लागत बंगलादेश में सामान्य व्यापार अथवा व्यापार कानूनों की अपेक्षा नहीं है। प्रकारवार लागत का निर्धारण उचित विभाजन आधार जैसे उत्पादन का मूल्य आदि के आधार पर किया जा सकता था जो अनेक जांचों के लिए अपनाई गई मानक पद्धति है जहां कच्चे माल वही होते हैं और अंतिम उत्पाद का मूल्य श्रेणियों, काउंटों आदि के आधार पर अलग अलग होता है।
- iv. कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान भारत में और अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया था। आवेदकों ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य किया है और संबद्ध वस्तुओं की सत्यापन योग्य लागत उपलब्ध कराई है। ये कीमतें बाजार के द्वारा प्रभावित होती हैं और इस प्रकार की कीमतों को अविश्वसनीय के रूप में केवल मानना नई शिप्पर समीक्षाओं की मूल भावना के विरुद्ध जाता है।

ज. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी उत्पादक/ निर्यातक के अनुरोधों को नोट करते हैं कि एक नई शिप्पर समीक्षा जांच में प्राधिकारी सामान्य मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। इसके अलावा उत्पादक/ निर्यातक बेड लिनन मामले का उल्लेख किया है। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि कंपनी यार्न के उत्पादन की काउंटवार लागत नहीं रखती है और यह कि इसने यार्न के विभिन्न काउंटों के लिए उत्पादन की औसत लागत उपलब्ध कराई है और यह कि बिक्री मूल्य के आधार पर, अलग अलग यार्नों के उत्पाद की लागत का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्राधिकारी उपर्युक्त अनुरोधों को नोट करने के बाद यह मानते हैं कि आवेदक ने उस कीमत से इनकार नहीं किया है और यार्न के अलग अलग काउंट की लागत में अंतर होता है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह मानते हैं कि उन परिस्थितियों में जिसमें विचाराधीन उत्पाद के अलग अलग पी सी एन पर तर्कसंगत तरीके से तुलना की जानी आवश्यक हो, प्राधिकारी ने ऐसा प्रयास विगत में किया है। पी सी एन स्तर पर सूक्ष्म मूल्यांकन अंतर्वोगत्वा जहां उसे उचित माना गया हो, का औसत निकाला जा सकता है। बेड लिनन मामला पी सी एन स्तर पर तुलना से नहीं रोकता है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि एन एस आर जांच में जहां आवेदक अलग अलग पाटन मार्जिन को स्थापित किये जाने के लिए बाद की अवधि में निर्यातक कर रहा है, बल्कि यह आवश्यक है कि तर्कसंगत तरीके से निष्पक्ष तुलना की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने यार्न के अलग अलग काउंटों के बीच कीमत में अंतर को नोट करते हुए आवेदक से यह अनुरोध किया कि वह यार्न के उत्पादन की काउंटवार लागत उपलब्ध कराये जो आवेदक उपलब्ध नहीं करा सके। इससे प्राधिकारी भारत में निर्यात किये गये यार्न के अलग अलग काउंटों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए बाध्य हो गये। प्राधिकारी यार्न के लिए उत्पादन की काउंटवार लागत का निर्धारण करने के लिए आवेदक द्वारा फिर से उल्लेख किये गये पद्धति को नोट करते हुए यह मानते हैं कि ऐसे परिदृश्य में जहां यार्न की कीमतें अपने आप में पाटनरोधी छान-बीन का विषय है, बिक्री कीमत पर उत्पादन की लागत से कुछ हिस्सों का विभाजन करने के लिए यह पद्धति उपयुक्त नहीं है। इस कारण से प्राधिकारी प्रकटन विवरण में किये गये उल्लेख के अनुसार यार्न के अलग अलग काउंटों के लिए सामान्य मूल्य स्थापित करने के लिए अपनी असमर्थता का फिर से उल्लेख करते हैं।

प्राधिकारी भारत में जांच की अवधि के दौरान यार्न के विभिन्न काउंटों की निर्यात कीमत के संबंध में आवेदकों के अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये लेन देन वार आयात आंकड़ों को साझा करने के लिए अपने अनुरोध को नोट करते हैं। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा विचार किये गये लेन देन वार आंकड़े डी जी – प्रणाली आंकड़े हैं जिसमें आयातक और निर्यातक का नाम प्राधिकारी के पास गोपनीय आधार पर उपलब्ध है। प्राधिकारी ने इन आंकड़ों पर फिर से विचार किया है और वह प्रकटन विवरण में दिये गये अनुसार अपनी टिप्पणियों की पुष्टि करते हैं। इस अनुरोध को नोट करते हुए कि आवेदक ने भारत को छोड़कर अन्य देशों में निर्यात किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल दो लेन देन में जहां भारत और अन्य देश में निर्यात किये गये यार्न काउंट एक जैसे हैं, भारत में निर्यात कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। बंगलादेश जूट गुड्स एक्सपोर्टर एसो. द्वारा यार्न की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के संदर्भ में किया गया अनुरोध केवल उचित कीमत जिन्हें उनके द्वारा व्यक्त किया गया है, के मत हैं और उनके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। आवेदक द्वारा भारत में कीमतों की तुलना उसी काउंट की अन्य आयात कीमतों से की जा सकती है जो वास्तविक सी आई एफ आंकड़ों के अनुसार है और इस कारण से वास्तव में वे आवेदक द्वारा दिये गये मत के बजाय विश्वसनीय है। जहां तक तुलना के लिए आयातों की सी आई एफ के बजाय पहुंच कीमत का संदर्भ का प्रश्न है, वह उपयुक्त नहीं है क्योंकि आवेदक उत्पादक/ निर्यातक द्वारा निर्यातों पर विचार पाटनरोधी शुल्क के बिना निर्यात के रूप में नहीं किया जा सकता है। आवेदक द्वारा किया गया ये निर्यात फिर भी बॉण्ड के अंतर्गत है बल्कि यदि आवेदक के दावे को स्वीकार नहीं किया जाता है तब शेष पाटनरोधी शुल्क की देयता के साथ है। अंतिम निर्धारण के लंबित रहने तक शून्य पाटनरोधी शुल्क की मान्यता नहीं हो सकती है। यह तथ्य कि आवेदक उत्पादक/ निर्यातक की कीमतों से निर्यात का 50 प्रतिशत से अधिक कीमत की तुलना उसी श्रेणी/ काउंट अर्थात् 28/1 सेकिंग और 14/1 सेकिंग के लिये अन्य निर्यातकों के साथ की जाती है, यह उस तथ्य का एक तर्कसंगत संकेत है कि आवेदक उत्पादक/ निर्यातक की निर्यात कीमतें अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों की तुलना में अधिक है। आगे आवेदक द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार तुलना की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिये, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक उत्पादक/ निर्यातक की निर्यात कीमत वास्तव में जांच की अवधि में सभी आयातकों से तुलना किये जाने पर अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी में है। ऐसी परिस्थितियों में, प्राधिकारी यह मानते हैं कि 5 प्रतिशत तर्कसंगत लाभ के साथ उत्पादन की औसत लागत के रूप में सामान्य मूल्य और जिस सीमा तक इन कीमतों को अपेक्षाकृत अधिक माना गया है तक समायोजित की गई कारखानागत निर्यात कीमत पर विचार करते हुए मूल्यांकन किये गये पाटन मार्जिन को सिफारिश की गई और मूल निर्धारण में लागू उत्पादकों/ निर्यातकों की नमूना न लिये गये श्रेणी के लिए शुल्क की श्रेणी में नोट किया गया।

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी आवेदक उत्पादक/ निर्यातक के लिए पटसन यार्न पर उत्पादक/ निर्यातक की नमूने न लिये गये श्रेणी पर शुल्क लगाने की सिफारिश भी करते हैं। पटसन सेकिंग बैग के लिए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि निर्यात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान सेकिंग बैग के कुल निर्यातों की बहुत कम मात्रा (1 प्रतिशत से कम) है और इसे वाणिज्यिक मात्रा बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्राधिकारी इस अनुरोध को नोट करते हैं कि एक नई शिप्पर समीक्षा जांच में आवेदक उत्पादक/ निर्यातक द्वारा बिक्री की मात्रा का कोई निर्धारण नहीं है और यह मानते हैं कि अलग अलग पाटन मार्जिन के मूल्यांकन में विश्वसनीय निर्यात कीमत को स्थापित करना अपेक्षित है। केवल कुछ सांकेतिक निर्यात करना प्राधिकारी को निर्यात कीमत की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए सक्षम नहीं बनाता है। मात्रा की आवश्यकता अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए कुछ न्यूनतम आरंभिक सीमा का निर्धारण करने के उद्देश्य से नहीं है। मात्रा की आवश्यकता निर्यात कीमत की विश्वसनीयता और उपयुक्तता स्थापित करने के लिए है। चूंकि वर्तमान जांचों का उद्देश्य अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करना है अतः सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत विचाराधीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा, निर्यात कीमत का निर्धारण का सहज संबंध निर्यात की मात्राओं से है। इस प्रकार से प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के पूर्व एक शर्त के रूप में निर्यात की मात्रा का निर्धारण नहीं किया है बल्कि सूचित की गई निर्यात कीमत की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए संगत मानदंडों में से एक मानदंड के रूप में निर्यात मात्राओं पर विचार किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि उत्पादक/ निर्यातक की नमूना न लिये गये श्रेणी के लिए सिफारिश किया गया शुल्क अलग अलग नमूना लिये गये उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सिफारिश किये गये शुल्क का एक औसत भी है और वह वर्तमान मामले में द्योतक भी होगा। इस कारण से, प्राधिकारी इस मामले के तथ्यों और आवेदक उत्पादक/ निर्यातक द्वारा सहयोग को नोट करते

हुए मौजूदा शेष श्रेणी के शुल्क के बजाय आवेदक उत्पादक/ निर्यातक के लिए भी सेकिंग बैग के उत्पादकों/ निर्यातकों की नमूना न लिये गये श्रेणी के लिए लागू शुल्क की सिफारिश करते हैं।

झ. निष्कर्ष और सिफारिशें

25. इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि दी गई परिस्थितियों में और मामले के तथ्यों को देखते हुए, उत्पादक/ निर्यातक पर केवल यार्न और सेकिंग बैग दोनों के लिए मूल जांच में निर्यातकों की नमूने न लिये गये श्रेणी के लिए सिफारिश किये गये अनुसार पाटनरोधी शुल्क के लिए विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, चूंकि यह शुल्क उत्पादक/ निर्यातक को आवेदन के आधार पर है अतः वास्तव में यह निष्पक्ष और उपयुक्त होगा। तदनुसार, मौजूदा प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार सिफारिश करते हैं :

i. क्रम संख्या 48 और 49 पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को दिनांक 15.01.2019 के सी. एन. सं. 03/2019 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से संशोधन किये गये अनुसार दिनांक 3.4.2017 से सी. एन. सं. 11/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) में उल्लिखित मौजूदा शुल्क तालिका में जोड़ा जाये।

क्र. सं.	शीर्षक/ उप शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	विविर्देशन	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई
48.	5307, 5310, 5607 और 6305	सेकिंग धैले	सभी रूपों और विनिर्देशनों में	बंगला देश	बंगला देश	रोमन जूट मिल्स लिमि.	एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी	125.21	यू.एस. डॉलर / मी. ट.
49.	5307, 5310, 5607 और 6305	यार्न	सभी रूपों और विनिर्देशनों में	बंगला देश	बंगला देश	रोमन जूट मिल्स लिमि.	एस एम पी इंटरनेशनल एल एल सी	97.19	यू.एस. डॉलर / मी. ट.

ii. दिनांक 7.5.2018 के सी. एन. सं. 24/2018 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के अनुसार जांच की अवधि अर्थात् 1.4.2018 से 31.3.2019 के दौरान किये गये यार्न और सेकिंग बैग के निर्यात को उपर्युक्त (i) के अनुसार नियमित किया जाये। मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमि. द्वारा 1.4.2018 से किये गये यार्न और सेकिंग बैग के निर्यात को आगे स्पष्ट करने के लिए उपर्युक्त (i) में यथाउल्लिखित पाटनरोधी शुल्क लगाया जायेगा जो दिनांक 3.4.2017 के सी. एन. सं. 11/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के मौजूद रहने के समय तक लागू रहेगा।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

FINAL FINDING

Subject: New Shipper Review under Rule 22 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 pertaining to Anti-Dumping Duty imposed on the imports of Jute Products” viz – Jute Yarn/ Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabric and Jute Yarn originating in or exported from Bangladesh, as requested by M/s Roman Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter) and M/s SMP International LLC (Exporter/Trader), USA initiated on 27.03.2018.

No.7/7/2018-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-

Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the Case

2. Whereas, in the original Anti-Dumping investigation, the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended, inter alia, imposition of anti-dumping duty on the imports of “Jute products” viz- Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags, originating in or exported from Bangladesh and Nepal, falling under Chapter 69 of the Customs Tariff Act, 1975, vide Final findings Notification No. 14/19/2015-DGAD dated 20th October, 2016. The Central Government notified the definitive anti-dumping duties vide Notification No. 01/2017-Customs (ADD) -Customs dated 5th January 2017 and Customs Notification No. 11/2017-Cus (ADD) dated 3rd April, 2017.
3. M/s Roman Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter) and M/s SMP International LLC (Exporter/Trader), USA filed an application for New Shipper Review (NSR) in terms of Rule 22 of the Anti-dumping Rules read with the Customs Tariff Act, requesting for a New Shipper Review (NSR) claiming individual dumping margin in respect of imports of the “Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single) and Jute Sacking Bags” originating in or exported from Bangladesh wherein AD measure has been imposed on “Jute Products” vide Customs Notification no. 11/2017-Cus (ADD) dated 3rd April, 2017.
4. The Authority, having been prima facie satisfied with the conditions laid down under Rule 22 of Anti-dumping Rules, initiated a New Shipper Review investigation, vide Notification No.7/7/2018-DGAD dated 27th March, 2018, for determination of individual dumping margin for the purposes of imposition of the anti-dumping duties levied on the dumped imports of “Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single) and Jute Sacking Bags” originating in or exported from Bangladesh, in respect of M/s Roman Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter) and M/s SMP International LLC (Exporter/Trader), USA.
5. Ministry of Finance notified the provisional assessment on all exports of the subject goods made by M/s Roman Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter) and M/s SMP International LLC (Exporter/Trader), USA till completion of the aforesaid NSR investigation vide Notification No.24/2018-Customs (ADD) dated 7th May, 2018.
6. The period of investigation for the purpose of this New Shipper Review was fixed as 1st April, 2018 to 31st March, 2019.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
 - (i) The Authority issued a public notice vide Notification No. 7/7/2018-DGAD dated 27th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject NSR anti-dumping investigation.
 - (ii) The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the applicant along with a copy of the exporter’s questionnaire and gave them opportunity to make their views known in writing, and filing relevant data in the prescribed Questionnaire, after expiry of the POI.
 - (iii) The Authority also forwarded a copy of the initiation notification to the High Commission of Bangladesh in India.
 - (iv) The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the known domestic producers in India and gave them opportunity to make their views known in writing.
 - (v) In response to the initiation notification, Questionnaire response was filed, M/s Roman Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter) and M/s SMP International LLC (Exporter/Trader), USA. IJMA representing the Domestic Industry of “Jute Products” in India also filed their representations.
 - (vi) The Authority made available non-confidential version of submissions/ information filed by the interested parties, in the form of a public file, kept open for inspection by interested parties.
 - (vii) The Authority held an Oral Hearing on 8th July, 2019 to provide an opportunity to interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6) followed by written submissions. The interested parties were allowed to present rebuttal rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Authority has considered submissions received from various interested parties appropriately.
 - (viii) All relevant Submissions/comments made by interested parties, during the course of this investigation have been considered and included in this disclosure statement.
 - (ix) The Authority issued a disclosure statement dated 30th August 2019 to the participating interested parties.

- (x) *** in the statement represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the AD Rules.

- (xi) Exchange Rate of Rs. 70.82 per USD has been adopted for POI.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

8. The product under consideration in the original investigation is 'Jute Products' comprising of Jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabrics and Jute Sacking bags. The Authority had recommended separate duty for each type of Jute products in the original investigation to producers.
9. The present investigation relates to proposed exports of Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single) and Jute Sacking Bags (of the two product types under the product under consideration as stated in Final Findings dated 20th October, 2016) by M/s Roman Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter) and M/s SMP International LLC (Exporter/Trader), USA as per the application filed by them before the Authority in accordance with the Act and the AD Rules.

D. SUBMISSIONS BY VARIOUS INTERESTED PARTIES AND DOMESTIC INDUSTRY :

10. Submissions by the Domestic Industry:

- i. IJMA submits that the applicant sought the present initiation without providing adequate and necessary information and evidence in terms of the Act, the AD Rules and Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994 ("ADA"), the understanding of the Directorate with regard to new shipper reviews that has prevailed in last five years, and the decisions of the Designated Authority and CESTAT with regard to new shipper.
- ii. The investigation was initiated on 18th Jan., 2018. The Authority had formulated new questionnaire format for NSR investigation even before the initiating the case on 25th April, 2018. While it is appreciated that the petition may have been filed before the issuance of the trade notice, nevertheless the applicant had an obligation to file updated information as per the trade notice after initiation. Despite having sufficient time and knowledge, the applicant did not revise information as per the new application proforma. What is surprising to see is that the questionnaire response filed for the prospective POI considered (much after the issuance of the trade notice) does not consider the format prescribed by the Authority
- iii. It has been claimed that the company is incorporated after the POI of the original investigation which is April 2014 to March 2015. However, the exhibit showing certification of incorporation shows that the company was incorporated on 3rd December 2014. This shows that the company was incorporated during the POI of the original investigation, however has claimed otherwise. Thus, the onus to demonstrate that it has not exported goods during the POI of the original investigation increases.
- iv. Further, till date, petition lacks any information and evidence to "show" that the applicants satisfy the requirements of Rule 22 and therefore, the present investigation must be terminated immediately.
- v. While a bona fide new shipper has the right to seek individual margins, at the same time, the Designated Authority needs to ascertain that the claims are bona fide and there is no abuse/ misuse/ circumvention of anti-dumping duties. It is for this reason that the applicant needs to be strictly put to establish that (a) they are genuine/bona fide exporters who have made bona fide sales (b) they have not exported goods in the original investigation and (c) they are not related to producer or exporter of subject goods who is attracting anti-dumping. In the instant case the applicant does not fulfil any of the criteria.
- vi. There is nothing in the application which shows that the essential requirements have been fulfilled. As held by the Hon'ble tribunal in the matter of H & R Johnson (India) Limited v. Designated Authority that "The word "show" is not meant to prescribe just a formality of a bare assertion by the applicant that the applicant is not "related".
- vii. The applicant has failed to provide evidence that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product, leave aside the evidences to establish the same. The requirement under the law is "to show", i.e., "demonstrate" and not "claim" or "state".
- viii. The applicant has also secured a trader for its product in USA and not India where it has made exports, or in Bangladesh, where the producer is located and where there are a large number of traders. A producer in Bangladesh had to search a trader all the way in US to export to India.

- ix. The applicants sought prospective period as period of investigation i.e., a period which is subsequent period to the initiation of investigation under Rule 22. Reference is made to the decision by Hon'ble CESTAT in Tiles case wherein the concept of prospective POR has been heavily criticized.
- x. By the reason of prospective period of investigation, the applicants have been able to manipulate and doctor the price by (a) making only ceremonial exports, i.e., 163 MT of exports, (b) at artificially high price. It is pertinent to note here that despite imposition of ant dumping duties, imports from Bangladesh has been significant. However the exporter has chosen to export low volume of subject goods which is insignificant in relation to total imports. It seems from the conduct of the applicant that they are not serious about the fate of the present matter and the current exercise is to merely an attempt to try luck if they can get a favourable margin. Their actions do not indicate that they are serious about exporting their products.
- xi. It appears from the reply of the exporter to questions on evidence of irrevocable contractual agreements of sales of the product under consideration to India that there is no commitment or contract with a prospective customer. This clearly indicates that not even a serious effort have been made by the applicants to export goods prior to the filing of the application.
- xii. The exports made by the applicants during the period of investigation in a new shipper review case must be bona fide commercial transactions of reasonable volume and price to be a basis for a dumping margin. It needs to be seen whether the sales under consideration is typical and will be representative of the new shipper's future sales. If a producer's or exporter's transactions involve price, quantities, and overall circumstances that do call into question the commercial viability of those sales, the genuineness of those sales, both in terms of value and volume, should be examined.
- xiii. Other country laws, such as US, Brazil, Canada, EU, Turkey, Taiwan and Vietnam etc are pertinent to note in this regard, which also provides that the transactions undertaken by the exporter should be bona fide and commercial in nature.
- xiv. The Authority has specifically prescribed that the quantities exported by the exporter should be in commercial quantity so as to receive an individual margin of dumping. The applicant had argued that the trade notice was issued recently and thus will have effect for future cases, it is submitted that the principle highlighted is not a new principle. The principle of actual exports been made in commercial quantity has been recognized by the Authority as well as Hon'ble CESTAT in past.
- xv. If an exporter is allowed a margin based only on a small volume of exports or based on an expectation of exports, this would open the scope for manipulation of prices by the exporter for obtaining a lower margin.
- xvi. There is no questionnaire response from the importers of the product under consideration. This further smoke conscious attempt to suppress the fact that a token export was made at unrealistic price in order to obtain a low or no dumping margin and thereafter aggressively dump the volumes
- xvii. The applicants have claimed excessive confidentiality without any good cause and for the sole objective of hiding information from the domestic industry and preventing the domestic industry from defending its interests.
- xviii. The applicants have provided no evidence whatsoever to demonstrate how the export price claimed by them is reasonable, reliable, representative and sufficient for the purpose of determination of export price.
- xix. There is no comparison with the imports into India to demonstrate reliability of the export price.
- xx. There appears grossly incomplete information with regard to both domestic selling price and cost of production of different types of the product to demonstrate adequacy and sufficiency of information and evidence. Nor the Designated Authority has information on record to account for differences in product types.
- xxi. Without prejudice, if the Authority concludes that applicant satisfies the condition and individual duties are justified, it is then submitted that the applicant may be given weighted average duties given to the cooperating companies not included in the sample in the original investigation, since the original investigation involved sampling.
- xxii. The domestic industry is additionally concerned for the reason that the domestic industry has sufficient reasons to believe that the quality and quantity of evidence and information provided by the exporters from Bangladesh has always remained a MAJOR ISSUE in all past investigations.

11. Submissions by the Applicant Producer/Exporter:

- i. The applicants fulfil the requirements to be treated as new shippers as stipulated in Rule 22 of the AD Rules which has its basis in Article 9.5 of the WTO AD Agreement. Rule 22 says that the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. The applicants meet these requirements.
- ii. It is reiterated that the applicant in the present NSR investigation did not export the subject goods to India during the original POI nor are related, with emphasis to all the connotations of the term 'relation' in the context of an NSR review as stipulated either in the rules or as notified by way of administrative trade notices, to any of the producers or exporters attracting anti-dumping duties on subject goods as notified therein.
- iii. Apart from the submission and certifications to substantiate the conditions of Rule 22, the applicant has submitted detailed documents which cover details and certifications on commencement date of production of subject goods by the company, audited reports and other statutory certifications, details of purchase of plant and equipments etc which will further establish the claims of the new shipper applicant.
- iv. The applicant fully meets the requirements of Rule 22 and further submit that the parties have no intention to dump the material in India and it is very essential to subject their bona fide exports to new shipper review for determination of individual margins based on the facts of actual exports made by them. The applicant has exported significant volume of the subject goods to India during the POI fixed. In case of applicants, the exports of PUC were in the range of 1100 to 1200 MT during the POI.
- v. NSR investigations are an integral part of the AD Agreement and also Indian AD Rules and the provision enables a new producer or exporter as defined therein to prove his case as a new exporter which will enable the Authority to examine whether there is any element of dumping in case of exports by such a new exporter. Allegation of IJMA against NSR is not of any basis.
- vi. Neither the Agreement nor the Rule stipulate any specific volume or price of export as a condition for determination of individual margins in an NSR. What makes an unrelated new shipper 'new' is precisely the fact that, during the original investigation period it did not export the subject goods to the territory where the subject goods were subjected to an anti-dumping investigation.
- vii. In fact the WTO Appellate Body clearly held against any laws framed putting in volume requirements in the conduct of a review as per Article 9.5 of the AD Agreement and the decision of the WTO Appellate Body in Mexico – Anti-Dumping Measures on Rice in this regard is binding on the Indian Authority as well read with the judgment of the Hon'ble Supreme Court in GM Exports matter.
- viii. In certain past cases, the Authority declined to grant individual margin to the new exporter as the Authority found the volume of exports by the new exporter as too insignificant to be considered as Commercially representative Quantity to be adopted for according individual Dumping Margin to the applicant Producer/Exporter. However, present case shows that the volume in the present case is very significant and the export price concerning such significant volume needs to be treated as inherently reliable.
- ix. The new shippers in the present case meet all the basic conditions as per Rule 22 and also the additional conditions emanated as part of the practices by the Authority in the recent past, both in terms of the requirement of reasonableness of volume and the trustworthiness of the price.
- x. It has been contended by IJMA that no individual margins should be determined for the new shippers here and in any case it cannot be anything other than the margins applicable on the 'non sampled category of exporters' as found in the original case. The contention has no legal basis. The rule clearly says that the Designated Authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers. It has been clarified by the Authority about its decision to adopt the margin for the non-sampled category in one of the NSRs concerning PUC while publishing the Final Findings concerning Melamine that it was '*constrained by the facts of the case had decided to only accord non-sampled category of AD duty to the applicant*'.
- xi. Any view taken under such constraining scenarios cannot become a rule especially in view of the clear legal position given in Rule 22 which requires the Authority to determine individual margins for the new shippers based on their relevant data.

- xii. It has been contended by IJMA that the investigation was initiated on 18th Jan., 2018 which is not correct. The case was initiated on 27.3.2018. Thereafter, it is contended that, despite having sufficient time and knowledge, the applicant did not revise information as per the new application proforma. The contention has no basis. The new proforma at point no 2 in the general instruction says that "This questionnaire is to be filled in by the new producer/exporters) for initiation of New Shipper Review Investigations". The petition in the present matter was filed before the introduction of the new format and even the case was initiated before the introduction of the new format. The new format was introduced vide TN dated 25.4.2018. Clearly, the format had a prospective effect and was not applicable to the present applicants.
- xiii. It has been contended by IJMA that it has been claimed that the company is incorporated after the POI of the original investigation, however, the exhibit showing certification of incorporation shows that the company was incorporated on 3rd December 2014 which shows that the company was incorporated during the POI of the original investigation, however has claimed otherwise. The contention apparently is the result of a typographical error in the reply at Q.3.h in the application. The petitioner intended to state that the commercial production of PUC commenced after the POI of the original investigation though the company was incorporated during the original POI. This is clearly stated at Question No 5 of the original application which read "M/s Roman Jute Mills Ltd Bangladesh was established 3rd December, 2014 to produce Jute Yarn and production of Jute Yarn started only on 8th August 2017". It is reiterated that the company did not export during the original POI and it has commenced production only in 2017 though it was incorporated in 2014.
- xiv. The contention of IJMA that present NSR was initiated without adequate evidences to prove the condition of Rule 22 is denied as bereft of any merit. The petition contained evidences to show that the new shipper did not export the subject goods to India during the original POI and the new shippers are not related to any producer or exporter who is attracting ADD. Also, significant time has elapsed since initiation of the present matter and the DI could not produce any piece of evidence to contradict the claims of the applicants.
- xv. The contention of IJMA qua the prospective POI has no basis. There has been significant number of NSRs initiated and concluded after the Tiles matter wherein the POI was fixed as prospective. The practice of prospective POI is correct in view of the provisions in Rule 22 which says that the Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule and this rule shall be otiose if the new shipper has to export before initiation of NSR.
- xvi. It has been contended by IJMA that by the reason of prospective period of investigation, the applicants have been able to manipulate and doctor the price by (a) making only ceremonial exports, i.e., 163 MT of exports, (b) at artificially high price. The contention has no basis. The applicant here has exported about 1100-1200MT (and not 163 MT as contended) of subject good which is a substantial volume and no such substantial export could have been possible at a manipulated price as alleged.
- xvii. It has been contended by IJMA that there are not any commitments to export to India shows the exporter is not serious. The contention has no basis. The exporter has exported about 1100-1200MT of subject goods during the POI which is a substantial volume.
- xviii. It has been contended by IJMA that the exports in NSR review must be a bona fide commercial transaction. It can be noted that the new shipper in the present matter exported significant volume to determine individual margins. This is without prejudice to our submission that the WTO Appellate body in Mexico-Rice matter has clearly ruled that the authorities cannot impose any volume requirements in the conduct new shipper reviews under the aegis of Article 9.5 of the AD Agreement which is the basis of Rule 22 of Indian AD Rules. However, the volume of exports in the present matter invariably fulfils certain parameters put in place by the Authority to examine the reasonableness of exports as evident in some of the recent NSR findings.
- xix. It has been contended by IJMA that there is no questionnaire response from the importers of the product under consideration and the applicants have claimed excessive confidentiality. Both the contentions have no basis. The importers in the present matter are not related parties of the applicant and the exporter in no way could have acted in a manner to ensure those parties file the IQ Response. The applicant claimed confidentiality as permissible in the Rule. In fact, the parties have given even the range of actual exports so that the DI gets a better idea of the case in hand.
- xx. It has been contended by IJMA that applicants have provided no evidence whatsoever to demonstrate how the export price claimed by them is reasonable, reliable. The contention has no legal or factual basis. The fact remain the applicant has exported significant quantity to India which itself proves the reasonability of the price. No such exports could have been possible with an artificially inflated price.

- xxi. It has been contended by IJMA that importer concerned have not cooperated with the Designated Authority and the Designated Authority cannot verify the information and satisfy itself that there is no compensatory arrangement between the exporter and importer. The contention has no basis. There are many cases concluded by the Authority where the importers did not cooperate but export price claimed by the exporters were verified and accepted. Non cooperation by the importer no way vitiates the credibility of price claimed by the exporter and there are other mechanisms used to verify the same such as data from customs/DGCI&S etc.
- xxii. It has been contended by IJMA that there appears grossly incomplete information with regard to both domestic selling price and cost of production of different types nor the Designated Authority has information on record to account for differences in product types. The contention has no basis. The EQ Response filed by the applicants has all applicable product type information.
- xxiii. It has been contended by IJMA that quantity of evidence and information provided by the exporters from Bangladesh has always remained a MAJOR ISSUE in all past investigations. Such assertions have no basis. It is felt that the Authority initiates and conducts an investigation when a case for such an investigation is clearly shown and not merely as alleged.

E. EXAMINATION BY AUTHORITY

12. Rule 22 of the Anti-Dumping Rules provides as follows –

“22. Margin of dumping, for exporters not originally investigated.

(1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.”

13. Article 9.5 of the WTO Agreement states as under –

“9.5 If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. Such a review shall be initiated and carried out on an accelerated basis, compared to normal duty assessment and review proceedings in the importing Member. No anti-dumping duties shall be levied on imports from such exporters or producers while the review is being carried out. The authorities may, however, withhold appraisement and/or request guarantees to ensure that, should such a review result in a determination of dumping in respect of such producers or exporters, anti-dumping duties can be levied retroactively to the date of the initiation of the review.”

14. In terms of the aforesaid Rule, provisions in the WTO Agreement and the past practice of DGTR, a New Shipper Review investigation is to be carried out under following circumstances for the purpose of determining individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the subject country attracting ADD:

- i. that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation, and
- ii. that exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product concerned.

15. In the instant case, M/s Roman Jute Mills Ltd. (Producer/Exporter) and M/s SMP International LLC (Exporter/Trader), USA has jointly filed an application before the Authority seeking individual dumping margin on “Jute Products” viz. Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single) and Jute Sacking Bags and requested for initiation of the new shipper review.

16. As regards the eligibility of the applicants as 'New Shippers', the Authority has conducted detailed examination of the claims made by the applicants including table study of various documents submitted with respect to data/information filed by them. Such examinations were conducted in view of the requirements of Rule 22 and the past practices of the Authority. No interested party has provided evidence of non-fulfilment of condition by the producer/exporter for NSR by way of any substantive evidences other than submissions. The Authority therefore proposes to hold that the applicants are eligible to seek a New Shipper Review in the instant case.

F. DETERMINATION OF INDIVIDUAL DUMPING MARGIN FOR THE APPLICANT

i. Overall sales of PUC and non PUI during POI of applicant producer

17. The producer/exporter have produced and sold both PUC (Yarn and Sacking Bag) and Non PUC (sacking cloth) during the POI as below:

	Yarn	Sacking Bag	Sacking Cloth
Production	***	***	***
Total Sales	***	***	***
Domestic Sales	***	***	***
Sales to India	***	***	-
Sales to 3 rd countries	***	-	-

The count wise/variety wise sales details are as under:

Sr. No.	PCN	India			3 rd Countries			Domestic		
		Volume (MT)	Value (BDT)	Price BDT/MT	Volume (MT)	Value (BDT)	Price BDT/MT	Volume (MT)	Value (BDT)	Price (BDT/MT)
	CB									
1	9 LBS 1 PLY	***	***	***	-	-	-	-	-	-
2	9 LBS 2 PLY	-	-	-	-	-	-	***	***	***
3	11 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
4	13 LBS 1 PLY & 16 LBS 1 PLY Mixed Lot	-	-	-	***	***	***	-	-	-
5	16 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
6	20 LBS 1 PLY	-	-	-	-	-	-	***	***	***
7	28 LBS 6 PLY	-	-	-	-	-	-	***	***	***
	CRT									
8	24 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
9	24 LBS 1 PLY & 26 LBS 1 PLY Mixed Lot	-	-	-	***	***	***	-	-	-
	Vegetable Oil Treated									
10	18 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
11	18 LBS 1 PLY & 16 LBS 1 PLY Mixed Lot	-	-	-	***	***	***	-	-	-
	Hessian									
12	9.5 LBS 1 PLY	***	***	***	***	***	***	-	-	-
13	10 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-

14	10 LBS 2 PLY	***	***	***	-	-	-	-	-	-
15	11 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
16	12 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
17	13 LBS 1 PLY	***	***	***	-	-	-	-	-	-
18	14 LBS 1 PLY	***	***	***	-	-	-	***	***	***
19	14 LBS 3 PLY	-	-	-	-	-	-	***	***	***
20	16 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
21	18 LBS 2 PLY	***	***	***	-	-	-	-	-	-
22	21 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
23	24 LBS 1 PLY	***	***	***	-	-	-	***	***	***
24	28 LBS 1 PLY, 18 LBS 1 PLY (Mixed Lot)	-	-	-	***	***	***	-	-	-
	Sacking									
25	10 LBS 1 PLY	-	-	-	-	-	-	***	***	***
26	11 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
27	13 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
28	14 LBS 1 PLY	***	***	***	-	-	-	-	-	-
29	16 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
30	16 LBS 3 PLY	-	-	-	-	-	-	***	***	***
31	18 LBS 2 PLY	***	***	***	-	-	-	***	***	***
32	20 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
33	24 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
34	28 LBS 1 PLY	***	***	***	***	***	***	-	-	-
35	28 LBS 3 PLY	***	***	***	-	-	-	-	-	-
36	28 LBS 1 PLY Vegetable Oil Treated	-	-	-	-	-	-	***	***	***
37	Sacking Bag	***	***	***	-	-	-	***	***	***
	Grand Total	***	***	***	***	***	***	***	***	***

ii. Normal Value

18.

- a. During the table study, the representatives of the company gave details in support of their claim related to major raw-material i.e. Jute purchase register prepared manually on daily basis, Production records i.e. Monthly Production reports submitted to Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA), copies of VAT Returns, sales records, Audited Accounts of the company for the POI. The practising Chartered Accountant certificate dated 15.07.2019 certified that Audited Accounts of the company for the POI and other Accounts/Financial Records are maintained and reported in accordance with accounting principles generally accepted in Bangladesh as per IASs referred by ICAB following BFRS. The basic records of the producers/exporters were by and large not professionally organised and were in Bangla as well, and required translation. However, the audited accounts of the POI has been considered as the basis for calculating cost of production. The company has not maintained separate accounting/cost records for the yarn, sacking cloth and sacking bags. Further, different type/ count of yarn (i.e. CB, CRT, CRT & Vegetable Oil Treated of different LBS and Count) sacking cloth and sacking bags (of different LBS and Count) are being produced by company and there is a variation in the sales prices among the different types of yarns and sacking bags.
- b. During the POI the company has produced *** MT of Yarn, *** MT of Sacking Cloth and *** MT of Sacking Bag. The raw-material consumption is booked by the companies for all the products together and no separate records were available for the different type/ count of yarn, sacking cloth and sacking bags. The raw-material consumption value has been allocated by the company based on the production quantity. The costs of utilities, packing materials, consumables, employee cost, depreciation, repairs & maintenance and other manufacturing overheads have been

allocated by the company to the product concerned on the basis of production value. Finance cost, other administration overheads and selling overheads have been allocated on sales value basis. As per the certified Appendix 5 in respect of M/s. SMP International LLC (Exporter/Trader) they are selling at profit and the same has been considered.

- c. The company is not maintaining separate records for the different type of products, however, keeping in view that the products which are sold at higher prices will also have higher cost, the cost of raw-material has been allocated based on production quantity, utilities and conversion cost has been allocated based on the production value and administration and finance cost has been allocated based on the sales value. Accordingly, the average cost of production of Yarn of all varieties, and Sacking Bag is worked out as BDT ***/MT, and BDT ***/MT respectively.
- d. The Authority notes that in the original investigation, the methodology adopted for computing 'Normal Value' of Yarn was on weighted average basis including all varieties of Yarn. The original investigation was conducted on a historical POI and opportunity for export price being adjusted for a favourable dumping margin was not available as could happen in a New Shipper Review. Therefore weighted average approach would be largely representative. The instant being a New Shipper Review wherein the Yarn varieties exported to India have different cost and price. Grade wise/count wise cost of production is an important parameter. The Authority notes that keeping in view that no count wise cost for different varieties of Yarn has been provided, it is not possible to compute the cost of production under consideration i.e Yarn on a count wise/variety wise and apply the OCT test on domestic or for 3rd country exports appropriately as the case may be. The Authority under these constraints could not establish a normal value for different variety of Yarns exported to India during the Period of Investigation. The Authority has dealt comments by the applicant producer/exporter and the submissions by the Bangladesh High commission and Domestic Industry in response to the disclosure statement in the later paras appropriately.

iii. Export Price

19. **The Authority reiterates that in the disclosure dated 30th August 2019 it was held that the producer/exporter** has exported to India through SMP International LLC, USA. It was noted that the shipper SMP International LLC, USA have sold each of the consignment after keeping some margin and their export sales are profitable. Hence for computation of net export price the at ex-factory level, sales of the producer to the shipper has been referenced. During POI the exporter has exported 36 consignments totalling to *** MT at an invoice value of *** US\$ (*** US\$/MT) (CNF) (ER *** BDT/\$). The adjustments have been claimed on the basis of actual expenses incurred on inland freight, Port expenses and bank charges. Based on the above the average net export price to India separately for Jute Yarn (all varieties) and sacking bags are *** and *** respectively.

The Authority notes that the producer/exporter has exported *** MT of Yarn which includes CB, Hessian and Sacking variety and *** MT of Sacking Bag during POI to India. The Authority notes that this correlates broadly with the DG-Systems data. The exports of Yarn and Sacking Bag by applicant exporter constitute 2-3% and 0-1% of the total imports from Bangladesh respectively.

The Authority has compared the prices of export of different varieties of Yarn on sample basis to the extent feasible during POI to India by the applicant with other exporters from Bangladesh to check if the export prices of different variety of Yarn of the applicant exporter were realistic. On comparing the export price of two specific types i.e. grade 14/1 and 28/1 sacking varieties of the applicant exporter with other exporters (account for 50-60% of total exports of applicant) it is noted that the export prices of the applicant exporter is higher by ***% and ***% respectively for these 2 specific grades (15-20% on an average). For other specific grades comparative data for such a comparison is not available. However, keeping the comparison of two grades as stated above, the Authority does not consider it appropriate to consider the export price of the applicant exporter reliable. As regards the other PUC type i.e. sacking bags as its quantity is just 0-1% of total imports of sacking bags from Bangladesh, it can not be considered as significant to establish a reliable export price of sacking bags to India. The post disclosure submissions of the applicant producer/exporter on consideration of export price and domestic industry are dealt in later paras appropriately.

iv. Dumping Margin

20. The Authority in the view of (iii) and (ii) above is constrained to establish an Individual dumping margin for the PUC under this investigation. The Authority however notes that the applicant producer has provided cost of production on an overall basis. If the weighted average cost of production for all varieties of Yarn exported to India with appropriate profit of 5% and export price of applicant exporter (appropriately adjusted in view of price variation stated in (iii) above) are compared, Dumping in the range of measure applied on non sampled producers/exporters in the original investigation would be evident. The export quantity of sacking bag to India is quite insignificant for establishing a reliable export price. The Authority proposes to consider these aspects appropriately in the final determination. The Authority has dealt post disclosure comments by the applicant producer/exporter and also the domestic industry on grant of individual dumping margin to the applicant producer/exporter in the later paragraphs appropriately.

G. Post Disclosure Comments**21. M/s TPM representing the domestic industry submitted the following post disclosure comments:**

- i. In NSR investigation it needs to be shown that exports made by the new shipper applicant during the period of investigation in a new shipper review case is bona fide commercial transaction, which is to be the basis for a dumping margin. The purpose was not to “ascertain the fair value of the merchandise but examine each sale for its commercial reasonableness
- ii. import volume is negligible of total imports. Moreover, the exporter must establish appropriateness and reliability of export price having regard to the export volume. The examination done by the Authority has shown that the export price is not representative
- iii. There is no reason bonafide or otherwise provided by the exporter to show how the exporter has been able to export goods at a higher price than the others when the same type of good is being imported at much lower price.
- iv. Other parameters that can be examined for appropriateness of the export price such as the price at which domestic industry has sold the product under consideration, unless the exporter demonstrates the reasons for differences in prices for different parties, Absence of compensatory arrangements between the importer and its buyer and exporter and importer, price at which the goods have been resold by the importer etc.
- v. applicants have made no efforts to seek questionnaire response from the importer in India. The importer in India has not come on board in this investigation. In view of no questionnaire response from the importers, the applicant has not established how the Designated Authority can ascertain appropriateness of the import price
- vi. the applicants have provided nothing which can be construed to imply that the applicants have shown to the Designated Authority that they satisfied the requirement under Rule 22

22. M/s M.S. Pothal & Associates representing the exporter/Producer submitted the following post disclosure comments:**A. The grounds for rejection of cost in the context of determination of normal value of the PUC produced by the applicant needs reconsideration as the rejection is not just and fair.**

- i. The legal framework of determination of dumping margin for an article exported by the producer or exporter is provided under Section 9A (6A) and rules to enable the process has been framed under Rule 10 by giving effect to Annexure I.

“The designated authority while determining the normal value, export price and margin of dumping shall take into account inter alia, the following principles -

1. The elements of costs referred to in the context of determination of normal value shall normally be determined on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country, and such records reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration”.(Emphasis added)

- ii. The above text of Annexure I to the Anti-dumping Rules clearly has its basis in Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-dumping Agreement. While interpreting the requirements of Article 2.2.1.1, the WTO Panel In Egypt – Steel Rebar noted that both Articles 2.2.1.1 and 2.2.2 “emphasize two elements, first, that cost of production is to be calculated based on the actual books and records maintained by the company in question so long as these are in keeping with generally accepted accounting principles but that second, the costs to be included are those that reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration.
- iii. In the present investigation, the applicant has submitted the cost information pertaining to the product under consideration as per the records maintained by the company which is as per GAAP. The Company has no system of maintaining the count wise cost for different varieties of Yarn because such a costing is not part of the normal course of business. Para 17. b. of the Disclosure acknowledges that the applicant is a producer of single type of PUC which is Jute Yarn and the cost of the same was available. Para 17.c. in the Disclosure statement as reproduced above nowhere says that the applicant failed to show that their cost records are maintained as per GAAP or any element of costs do not reflect the cost associated with the PUC which is Yarn (Jute Products) in terms of any particular element of cost. Further please note that company produces yarn of three varieties namely CB, Hessian and Sacking, within these three varieties there are number of counts in each of three varieties, and in counts there are number of plies, hence for a small scale company it is not viable to maintain type wise raw material cost for each of the PCNs. The observation is only that it is not possible to compute the cost of production of different types of yarn on count wise/variety wise as the count wise costing is not provided. This cannot be a fair ground for the rejection of cost concerning PUC.

- iv. As the applicant has provided the cost for PUC which is Yarn here, the observation that the relevant cost for PUC is not available needs reconsideration though at later part in the Disclosure the Authority noted that the applicant has provided weighted average cost for the PUC. As far as cost of different types of yarn is concerned, the applicant suggested that the main cost is on account of raw materials and the cost of raw material could have been allocated based on sales value ratio concerning different types of yarn. This is based on the principle that the product which has a higher realization in the market has a higher cost as well. Such a method is reasonable and could have enabled the Authority to determine even the type wise cost of yarn though the requirement of Rule is to determine the cost for the PUC and not for its *inter se* types. Without prejudice, type wise cost of yarns on the above basis is enclosed.
- v. The applicant in the context of type wise cost also submits that Annexure II to the WTO AD Agreement clearly addresses a situation where the information provided may not be ideal in all respects at para 5 of Annexure II. Absence of type wise cost needs to be seen in this context. The Agreement clearly says that even though the information provided may not be ideal in all respects, this should not justify the authorities from disregarding it, provided the interested party has acted to the best of its ability. In the present case, the applicant has acted to best of its ability as the applicant has provided cost as per its records at PUC level and also provided type wise cost on a proper allocation basis. The determination of cost on a type wise basis could be a matter of allocation and a pragmatic and normally followed methodology for the same was also suggested.
- vi. Notwithstanding the above, the moot question which emanates from the observation of the Authority in para 17.c. is that can the Authority adopt a different approach in the determination of cost of the article under investigation in the context of normal value in a New Shipper Review for the primary reason that POI of the present NSR is a prospective period which is known to the applicant at the time of exports or the investigation in question is a new shipper review?. Our respectful submission is that such an approach has no legal sanctity and the methodologies provided in Annexure I are applicable in every determination of dumping margin be it a fresh investigation or new shipper review. Also, the nature of investigation per se which is NSR here does not vitiate or prejudice the reasonableness of cost in any manner nor nature of investigation can be a ground to dispute the reasonableness of cost. Nature of review cannot be a ground per se to determine the reasonableness of cost and reasonableness of cost has to be examined based on reasonableness of various elements of cost involved in the claims of the applicant and cannot be merely on a presumptive basis citing the nature of investigation. It is respectfully submitted that such a view goes against the purpose of new shipper review as envisaged in Article 9.5 of the AD Agreement and such a view can seriously prejudice the rights of the applicant and the prospective POI in the present case was determined by the Authority as permissible under the law. Once the POI is determined as permissible in the law, the same cannot be a ground to doubt the credibility of cost and price claimed by the applicant and such a presumption goes against the premises of present initiation. It is requested that the normal value may kindly be determined based on principles envisaged in Annexure I to the Rules viz. determination of cost in the context of normal value like any AD investigation and an NSR applicant should not be placed on a different pedestal while determining his cost.
- vii. It is also submitted that the requirement under the law is to determine dumping margin for the product under consideration and not type wise and in that context, disregarding the cost of PUC which is as per the records maintained by the company based on GAAP is not justified at all. In EC – Bed Linen, the WTO Appellate body found as follows;

"53. We see nothing in Article 2.4.2 or in any other provision of the Anti-Dumping Agreement that provides for the establishment of 'the existence of margins of dumping' for types or models of the product under investigation; to the contrary, all references to the establishment of 'the existence of margins of dumping' are references to the product that is subject of the investigation. Likewise, we see nothing in Article 2.4.2 to support the notion that, in an anti-dumping investigation, two different stages are envisaged or distinguished in any way by this provision of the Anti-Dumping Agreement, nor to justify the distinctions the European Communities contends can be made among types or models of the same product on the basis of these 'two stages'. Whatever the method used to calculate the margins of dumping, in our view, these margins must be, and can only be, established for the product under investigation as a whole. We are unable to agree with the European Communities that Article 2.4.2 provides no guidance as to how to calculate an overall margin of dumping for the product under investigation" (Emphasis added)
- viii. Thus, absence of type wise/count wise cost maintained by the applicant for the *inter se* types of the PUC cannot be a ground to reject the cost of the PUC as maintained by the applicant. Had the applicant failed to submit the cost of PUC as per the two main requirements i.e records as per GAAP and reasonableness of cost as provided in the Rule, it would have been a different issue. In the present case, the applicant has provided required data as per the Rule to determine normal value and the rejection of cost for the grounds given therein are not justified at all and we crave before the Authority to reconsider the same in the interest of justice and fairness.

B. The grounds for rejection of export price as claimed the applicant needs reconsideration as the rejection is not just and fair.

- i. As a primary submission, it is reiterated that the applicant has exported significant volume of subject goods and no such volume level could have been possible at a price unreasonably higher than the prevailing market price. The applicant exported at a price comparable to the prevailing market prices and it was no way an inflated price.
- ii. The comparison of export price of the applicant with some exports made by the other exporters as a sample is not a fair method to check the reliability of the export price of the applicant as the sample selected is not representative at all in terms of volume and level of trade. The applicant vide its letter dated 1.9.2019 requested for the entire data of exports of PUC from Bangladesh for a proper comparison but the same is not provided. Any such comparison has to be on a reasonable basis and the sample selected here are miniscule. Until and unless, the export price of the applicant is compared to a significant portion of total export of the same kind of PUC from Bangladesh to India during the POI made by other exporters, no fair view can be arrived without any distortion in the approach.
- iii. The export price as relied upon by the Authority in the corroborative sample appears to be at CIF level and not at landed level. The PUC is attracting ADD for majority of the exporters and any price comparison needs to be made by taking such duty into consideration. The applicant exported the PUC subject to the present review and no ADD was applicable on such PUC at the time of imports. Thus, the import price of an importer importing from an exporter in the residual category of exporter, who got the lowest duty and exporter with no duty cannot be compared at the same breadth. The element of duty clearly comes in the price at the end of the importer and any comparison has to be made at the landed level to see what the actual price of imports was. Hence, the observation that the price of the applicant was 15-20% higher and hence not reliable needs reconsideration based on facts of trade.
- iv. It is to be noted here that the applicant also exported the subject goods to India in the Post POI period. The post POI imports do not have any bearing on the determination of dumping margin and even the price during Post POI reflects such level of prices which is comparable to the prices in POI. It may be please be noted that the company has exported substantial quantity in the post POI period which also shows the reliability and consistency of price. We request the Authority to consider post POI price of export also to examine the veracity of export price claimed by the applicant for the POI. The price during the post POI would clearly show that the allegation of exporter inflating the price to get a lower margin is completely baseless.
- v. We are further enclosing a circular issued by Bangladesh Jute Mills Corporation, wherein it can be seen that the price for CB 10 LBS/1 Ply is listed as *** US\$ per MT as international export price. Our price during POI was BDT *** which is equal to US\$ *** per MT. It can be seen that our price is comparable to Govt. decided price. The relevance of this circular is that though such prices are not strictly binding as a bench mark, such prices clearly indicated the price range prevailing in the market and the applicant also exported at a realistic price comparable to such notified price to India. It cannot be said that the applicant exported at an unrealistic price not at par with what other exporters were considering.
- vi. We are further enclosing a letter issued by Bangladesh Jute Goods Exporters' Association, wherein they have disclosed the international price of 14/1 and 28/1 sacking quality yarns, this price also matches our export price during the POI. This is also indicative of the fact that the applicant was not exporting at any artificial prices to India and such prices were very prevalent in the market parlance.
- vii. Thus, based on the above it is submitted that the view of the Authority on the export price claimed by the applicant as proposed in the Disclosure needs reconsideration based on facts and we crave for the same in the interest of justice and fairness.

C. The applicant could provide verifiable information for the purpose of determination of individual dumping margin in case of its exports to India. Any proposal for an alternate methodology should be seen in this context.

- i. Rule 22 of Anti-dumping Rules governing New Shipper Reviews clearly says *the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers*. The requirement is clearly determination of individual dumping margins and it cannot be adaptation of some other margins determined in the past or for some other parties.
- ii. It is also respectfully submitted that the Authority has in a recent NSR concerning Janata Jute Mill NSR case concerning the same PUC had determined Individual Margin based on margins for non sampled category. However, the Authority clarified its position on the said determination on the course of an eventual investigation concerning Melamine as follows; *"The Authority notes that in the same determination the Authority had emphasised the need to establish reasonableness and credibility of export price and constrained by the facts of the case had decided to only accord non-sampled category of AD duty to the applicant."*

- iii. Thus, the adaptation of margin for the non-sampled category in the Janata Jute Mill case was the result of certain factual constraints in the said case and there are no such constraints in the present matter. The applicant has provided details to determine individual dumping margin and the exports by the applicant were substantial during the POI. Any view taken under some constraining scenarios in some other cases cannot become a rule especially in view of the clear legal position given in Rule 22 which requires the Authority to determine individual margins for the new shippers based on their relevant data. Neither the Rule nor the anti-dumping Agreement provides for any provision which enables the Authority to adopt a margin for the NSR applicant other than that of the individual margin based on its own data like margin of the non-sampled category of exporters in the original case.
- iv. Without prejudice, it is our respectful submission that the Authority shall be in a position to determine individual margin for the applicant and there shall be no need to adopt any other basis or adoption of best available information after proper consideration of these comments. The applicant would like to draw the attention of the Authority to Article 6.8 of the Anti-Dumping Agreement which allows investigating authorities to make determinations on the basis of facts available only in such cases where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information, or significantly impedes the investigation. None of the above conditions is applicable to the NSR applicant as the applicant have fully cooperated with the Authority and were willing to provide any other information that may be required by the Authority. Following WTO decisions are relevant in this regard;
 - a. In Argentina – Ceramic Tiles, the Panel held that "It is clear to us, and both parties agree, that an investigating authority may disregard the primary source information and resort to the facts available only under the specific conditions of Article 6.8 and Annex II of the AD Agreement. Thus, an investigating authority may resort to the facts available only where a party: (i) refuses access to necessary information; (ii) otherwise fails to provide necessary information within a reasonable period; or (iii) significantly impedes the investigation."
 - b. In US – Steel Plate, the Panel analyzed the extent of the limitation that paragraph 3 of Annex II puts on investigating authorities' right to reject information submitted and instead resort to facts available and did not accept the United States' position that 'information' in Article 6.8 means all information, such that Members have an unlimited right to reject all information submitted in a case where some necessary information is not provided.
 - c. The Panel in EC - Salmon (Norway) drew support from US – Hot-Rolled Steel and US – Steel Plate held that "Paragraph 3 of Annex II directs investigating authorities to take all submitted information into account for the purpose of its determinations when it is: (i) 'verifiable'; (ii) 'appropriately submitted so that it can be used in the investigation without undue difficulties'; (iii) 'supplied in a timely fashion'; and, where, applicable, (iv) 'supplied in a medium or computer language requested by the authorities'. Thus, paragraph 3 of Annex II calls upon investigating authorities to take into account all information that satisfies three, or sometimes four, cumulative conditions when making determinations. It follows that where all of the conditions are satisfied, an investigating authority will not be entitled to reject information submitted when making determinations."

23. Comments to disclosure filed by Bangladesh High Commission:

- i. The three companies concerned filed all relevant information pertaining to Normal value of subject goods in Bangladesh and Export price of subject goods to India and to other countries for the period of Investigation in the prescribed Exporter Questionnaire Response format and in timely manner. They cooperated with the Authority and provided with necessary information for determination of individual dumping margin.
- ii. Despite full cooperation and submission of all relevant information, the Disclosure statement proposes not to determine normal values and export prices for our company. A perusal of the Disclosure statement shows that the Authority asserted that information pertaining to both normal value and export price of the producer/exporter are not reliable for the fundamental reason that the POI of the investigation was a prospective period or the applicant had the knowledge of the POI though we submitted verifiable data as maintained by the companies. The very purpose of the new shipper review is not to subject a new shipper to punitive residual duties in an earlier investigation and to provide an opportunity to prove his price behaviour in a prescribed POI for determination of individual margin of dumping. Therefore it would be a very unfair to disregard the normal value and export price of the producer/exporter on the ground that the investigation was done in a prospective period.
- iii. The applicants have submitted verifiable cost of the "jute products" which was the product Chartered Accountant vide its certificate dated 15.07.2019 certified that Audited Accounts of the company for the POI and other Accounts/Financial Records are maintained and reported in accordance with accounting principles generally accepted in Bangladesh as per IASs referred by ICAB following BFRS. Since the producers and exporters maintain their data in a particular manner historically, they could not have changed their accounting

methodologies only for this investigation. The records maintained by the applicants do not follow such type wise costing and such type wise cost is not a requirement of general business or business laws in Bangladesh. The type wise cost could have been determined based on a proper apportionment basis such as value of production etc. which is a standard method adopted for many investigations where the raw materials are same and the value of end product varies depending upon the grades, counts etc.

- iv. The companies had exported significant quantities of the subject goods to India and to other countries during the POI. The applicants have acted to the best of their ability and provided verifiable cost of the subject goods. The prices were driven by the market and merely terming such prices as unreliable goes against the spirit of New Shipper Reviews.

H. Examination by Authority

24. The Authority notes the submissions of the producer/exporter that in a new shipper review investigation the Authority cannot adopt a different approach to evaluate normal value. Further, the producer/exporter has cited the bed linen case. The applicant has also stated that company does not maintain count wise cost of production of yarn and that it has provided the average cost of production for different counts of yarn and that based on sales value, cost of product of different yarns could be evaluated. The Authority after noting the above submissions holds that the applicant has not denied that price and cost of different count of yarns vary. The Authority further holds that in situations which warrant an apple to apple comparison at different PCN's of PUC, the Authority has undertaken such an exercise in past. The granular evaluation at PCN level may ultimately be averaged out wherever considered appropriate. The bed linen case does not prohibit a PCN level comparison. The Authority also holds that in a NSR investigation where the applicant is exporting in a prospective period to have an individual dumping margin established, it is rather imperative that fair comparison at apple to apple be undertaken. The Authority in the instant case, noting the price variation amongst different counts of yarn, requested the applicant to provide count wise cost of production of yarn which the applicant could not provide. This constrained the Authority to established the normal value for different counts of yarn exported to India. The Authority, noting the methodology reiterated by the applicant to determine count wise cost of production for yarn, holds that in a scenario where the prices of yarn itself are subject of AD scrutiny, methodology to apportion some parts of cost of production on the sales price is not appropriate. Therefore, the Authority reiterates its inability to establish normal value for different counts of yarn as stated in the disclosure statement.

The Authority notes the submissions of applicants regarding export price of different counts of yarn during POI to India and its request to share the transaction wise import data adopted by Authority. The Authority clarifies that transaction wise data considered by Authority is DG-Systems data wherein the name of importer and exporter is available to the Authority on a confidential basis. The Authority has revisited the data and confirms its observation as given in the disclosure. Noting the submission that applicant has exported to countries other than India, the Authority notes that only in two transactions, where yarn count exported to India and other country is identical, the export price to India is higher. The submission by the Bangladesh Jute Goods Exporters Association on international prices of yarn are merely opinions of reasonable price expressed by them and are not supported by any evidence. The prices to India by the applicant are compared with other import prices of same count which are as per the actual CIF data and therefore are infact credible rather than an opinion produced by the applicant. As regards referencing landed price instead of CIF of imports for comparison, the same is not appropriate as exports by the applicant producer/exporter cannot be considered as exports without an AD duty. These exports made by applicant are nevertheless under bond but are with a liability of residual ADD if applicant claims are not accepted. There cannot be an assumption of nil ADD pending a final determination. The fact that more than 50% of exports by applicant producer/exporter prices are compared with other exporters for same grade/count i.e. 28/1 sacking and 14/1 sacking, this is a reasonable indication of the fact that export prices of applicant producer/exporter are higher than other producers/exporters. Further to enhance the reliability of comparison as requested by the applicant, the Authority notes that export price of the applicant producer/exporter is infact in the higher category when compared with all importers in the POI. Under such circumstances, the Authority holds that the dumping margin evaluated considering normal value as average cost of production with 5% reasonable profit and ex-factory export price adjusted upwards to the extent the prices are observed to be higher is noted to be in the range of measure for non-sampled category of producers/exporters recommended and applicable in the original determination.

The Authority in view of the above, recommends measure of non-sampled category of producer/exporter on Jute Yarn for the applicant producer/exporter as well. For Jute Sacking Bag, the Authority holds that the quantum of exports is a miniscule quantity (less than 1%) of the total exports of sacking bag during the POI and this cannot be considered as commercial quantity sale. The Authority notes the submission that there is no prescription of quantum of sales by an applicant producer/exporter in a new shipper review investigation and holds that the evaluation of individual dumping margin requires establishing a reliable export price. Merely undertaking some token exports does not enable the Authority to establish credibility of the Export Price. The requirement of volumes is not for the purpose of prescribing some minimum threshold for determining individual dumping margin. The requirement of volumes is to establish reliability and appropriateness of the export price. Since the purpose of the present

investigations is to determine individual dumping margin, the normal value and export price are the critical issues under consideration. Further, determination of export price has inherent linkage to the export volumes. Thus, the Authority has not prescribed export volumes as a condition precedent to determination of dumping margin, but has considered export volumes as one of the relevant criteria to determine appropriateness of export price reported. The Authority holds that the measure recommended for non-sampled category of producer/exporter is also an average of the measure recommended for individual sampled producers/exporters and would also be representative in the instant case. The Authority, noting the facts of the case and cooperation by the applicant producer/exporter, therefore recommends the measure applicable for the non-sampled category of producers/exporters of sacking bag for the applicant producer/exporter as well instead of the existing residual category measure.

I. Conclusions and Recommendations

25. The Authority therefore holds that in the given circumstances and facts of the case, the producer/exporter can only be considered for an AD measure as recommended for the non-sampled category of exporters in original investigation both for Yarn and Sacking Bag. Further, since this measure is based on application to the producer/exporter, this would indeed be fair and appropriate. Accordingly the existing Authority recommends as under:

- i. Following entries at S. No. 48 and 49 be added to the existing duty table mentioned in C.N. No. 11/2017Customs (ADD) dated 3/4/2017 as amended through C.N. No. 03/2019-Customs (ADD) dated 15/1/2019.

S. No.	Heading/sub heading	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit
48.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	In all forms and specification	Bangladesh	Bangladesh	Roman Jute Mills Ltd.	SMP International LLC	125.21	US\$/MT
49.	5307, 5310, 5607 or 6305	Yarn	In all forms and specification	Bangladesh	Bangladesh	Roman Jute Mills Ltd.	SMP International LLC	97.19	US\$/MT

ii) Export of yarn and Sacking Bags made during POI i.e. 1/4/2018 to 31/3/2019 in accordance with the C.N. No. 24/2018-Customs (ADD) dated 7/5/2018 be regularised in accordance with (i) above. To further clarify the exports of yarn and sacking bag made by M/s Roman Jute Mills Ltd. w.e.f. 1/4/2018 will be subjected to AD duty as stated in (i) above which would be conterminous with the existence of C.N. No. 11/2017-Customs (ADD) dated 3/4/2017.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General